खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-01) / अंक-33

शुक्रवार 10 जून, 2016 / 20 ज्येष्ठ, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-01) में अंक 32 से अंक 34 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

सत्र–4 भाग (1) शुक्रवार, 10 जून, 2016/20 ज्येष्ठ, 1938 (शक)		अंक–33
1.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	1–13
2.	उपाध्यक्ष का निर्वाचन	13–17
3.	विशेष उल्लेख	26–40
4.	विधेयक का पुरःस्थापन	40–43
5.	अल्पकालिक चर्चा (नगर निगमों में तथाकथित भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन पर)	44–74
5.	सदन की समिति का गठन	74–116

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 भाग (1) **शुक्रवार, 10 जून, 2016/20 ज्येष्ठ, 1938 (शक)** **अंक–33**

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री गिरीश सोनी

19. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
20. श्री राजेश ऋषि
21. श्री नरेश बाल्यान
22. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
23. सुश्री भावना गौड़
24. श्री सुरेन्द्र सिंह
25. श्री विजेन्द्र गर्ग
26. श्री प्रवीण कुमार
27. श्री मदन लाल
28. श्री नरेश यादव
29. श्री करतार सिंह तंवर
30. श्री प्रकाश
31. श्री अजय दत्त
32. श्री दिनेश मोहनिया
33. श्री सौरभ भारद्वाज
34. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
35. श्री सही राम
36. श्री नारायण दत्त शर्मा
37. श्री अमानतुल्लाह खान
38. श्री राजू धिंगान
39. श्री मनोज कुमार
40. श्री नितिन त्यागी
41. श्री एस.के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
44. श्रीमती सरिता सिंह
45. मो. इशराक
46. श्री श्रीदत्त शर्मा
47. चौ. फतेह सिंह
48. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 भाग (1) शुक्रवार, 10 जून, 2016/20 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक–33

सदन अपराह्न 2.02 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस सदन की सदस्य सुश्री राखी बिड़ला ...व्यवधान विजेन्द्र जी, कोई विषय है। मैं ले लूं उसको?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बताइये ना आप। ना आप हमारा अटैंशन लेते हैं न आप...

अध्यक्ष महोदयः अभी बता रहा हूं, दो मिनट रूकिये जरा, मैं दुबारा पढ़ रहा हूं, आज इस सदन की सदस्य सुश्री राखी बिड़ला का जन्म दिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तित्व तथा राजनैतिक जीवन में नई ऊचाइयॉ प्राप्त करें।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, ...(व्यवधान) आ रहा हूं भईया, उस विषय पर। मैंने विजेन्द्र जी, आपसे कहा, ये उपाध्यक्ष के निर्वाचन का काम एक बार पूरा हो जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः निर्वाचन से पहले ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि कॉलिंग अटैंशन किसी महत्वपूर्ण विषय पर ये मैंबर का अधिकार है। इसलिए आप मेरा ये अनुरोध है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जब अधिकार रहता है, जब तो आप सदन में होते नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, मुझे मालूम है कब मुझे रहना है कब नहीं रहना अध्यक्ष जी, और इस सदन में क्या हो रहा है, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा इतना अनुरोध है कि ये जो विषय यहां मैंने रखा है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः सर, मैंने कल एक बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाया था, एम एम खान का जो मर्डर हुआ है, एक ईमानदार अफसर को, बी. जे.पी. के नेताओं ने मिलके उनको मरवा दिया, उनके इंसाफ के लिए आप समय दीजिए, उस पर चर्चा करवाइये। इससे गम्भीर विषय हो नहीं सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं तो आपको शायद कभी संतुष्ट कर नहीं पाउंगा, कितना ही समय दे लूं, ...(व्यवधान) चलिए मैं दे रहा हूं। उस पर रूलिंग,अभी दे रहा हूं रूलिंग उस पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बता दीजिए अगर मैं ठीक नहीं हूं। ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी इसकी पूरी जांच करवाइये, इस केस की। ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने तीन घंटे पहले नोटिस दिया है, आप ये बता दीजिए ये लाने दिया जायेगा कि नहीं लाने दिया जायेगा? और ये भ्रष्टाचार का मामला है...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदयः इस विषय पर कल रूलिंग दी तो थी मैंने। ...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, अगर गुप्ता जी चाहते ही हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो तो हमारे विधायक सुरेन्द्र सिंह कमांडो ने कल जो मुद्दा उठाया था, एक लैटर मेरे सामने है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं, मिस्टर पी. शंकर रेड्डी बाबू ने जो चीफ सीई.ओ. ऑफीसर है, दिल्ली कन्टून्मैन्ट बोर्ड के, उन्होंने आज एल.जी. को लैटर लिखा है कि भाजपा के पूर्व विधायक करण सिंह तंवर का हाथ श्री एम. एम. खान की हत्या की साजिश में दिखता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं अभी अपनी रूलिंग दे रहा हूं उस पर। आप बैठिये। अगर आप पहले यही चाह रहे हैं, अच्छा, अब आप प्लीज बैठिए, मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं। ....(व्यवधान) नहीं बहुत बार दिया है। डेढ़ साल का रिकार्ड निकाल देंगे उस डेढ़ साल के रिकार्ड में कितना समय दिया है, मैं निकाल दूंगा,...(व्यवधान) कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना

चाहूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के लिए नियम 280 के तहत सूचना देने का प्रावधान है,...(व्यवधान) आप सुन लें या बोल लें।...(व्यवधान) कमांडो सुरेन्द्र जी, बैठिये दो मिनट प्लीज...(व्यवधान) विजेन्द्र जी मैं रूलिंग दे रहा हूं अभी कोई वॉस्ट एप्रोच नहीं है, आप बार–बार जो मर्जी... आप अगर वॉस्ट रहते तो... मेरे पास कोई ईलाज नहीं है। मैं पूरा समय देता हूं। हर तरीके से समय देता हूं। चलिए, नियम–54। सरकार ने, खुद शीला दीक्षित के समय का भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार ने लिखा है, अभी आप बैठिए।...(व्यवधान) अभी दो मिनट बैठिए।

मुझे नियम–54 के अंतर्गत श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का ध्यानाकर्षण का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के लिए नियम–280 के तहत सूचना देने का प्रावधान है। आज समय का अभाव है। कल प्रारम्भ हुई एक अल्पकालिक चर्चा लम्बित है तथा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर अल्पकालिक चर्चा होनी है। अतः मैं श्री गुप्ता के नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) सुरेन्द्र जी, प्लीज बैठिए, विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज. ..(व्यवधान) अब बैठ तो जाइय...(व्यवधान) सुरेन्द्र जी, दो मिनट बैठिये। एक बार बात सुन लीजिए, बैठ तो जाइये कम से कम, बैठने में कोई दिक्कत है क्या?

श्री मनीष सिसोदिया(उप मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, सीबीआई इनकी, ए.सी.बी. पर ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कर लें जांच और अगर ये ना करवा पा रहें हैं तो हम करवा देते हैं। ये कह दें कि हमसे नहीं हो

रही। ए.सी.बी. में इतनी एफ.आई.आर. करवा रखी हैं इन्होंने। हमारे विधायकों के खिलाफ तक एफ.आई.आर. कराते हैं। इनसे शीला सरकार के घोटालों के खिलाफ एफ.आई.आर. नहीं करवाई जा रही इनसे ए.सी.बी. में। क्यों नहीं करवा रहे ए.सी.बी. में एफ.आई.आर? किसने रोक रखा है? बताएं अपने एल. जी. साहब से पूछके कि किसने रोक रखा है इनको? विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए सदन में चर्चा होती है क्या? विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. होती है तो उपराज्यपाल महोदय चुपचाप सौंप देते हैं ए.सी.बी. को। क्यों नहीं सौंपा अभी तक शीला सरकार का क्या लेना–देना है इनका शीला सरकार के घोटाले से? ये बतायें यहां पे।

...(व्यवधान)

उप–मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कराइए ए.सी.बी. से जांच। जांच कराइए। हम तो करा लेगें। अगर हिम्मत है तो आप भेज दीजिए। नही।तो हम भेज रहे हैं। आपके उपराज्यपाल में हिम्मत है तो भेज दीजिए उसको ए.सी.बी. को। आप लोग नहीं करा पाओंगे। डरते हो आज शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से!

...(व्यवधान)

उप–मुख्य मंत्री : इनकी हिम्मत नहीं है जांच कराने की।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये कितना बडा भ्रष्टाचार है !

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आइए, इस कुर्सी पर आ जाइए। आइए प्लीज। मुझे मालूम है कितना बड़ा है। आइए। नहीं, आइए। वहां आइए। अपनी कुर्सी पर आइए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आइए प्लीज।

...(व्यवधान)

उप–मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चौबीस घंटे की चुनौती दे रहा हूं। चोबीस घंटे में या तो जांच सौंप दें। नहीं तो मैं उपराज्यपाल साहब को चिट्ठी लिखूंगा।

...(व्यवधान)

(विजेन्द्र गुप्ता जी अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने वेल में आए।)

अध्यक्ष महोदय : आइए, आप आइए। मैं रूलिंग दे चुका हूं इस पर। आपको जवाब भी मिल गया।

...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं। पूरे देश के अंदर भारत के आजाद इतिहास में आम आदमी पार्टी की सरकार शायद अकेली सरकार है... जितना कमिटमेंट हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी का किसी भी सरकार का.....। उसी से डर कर जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने स्ट्रॉग आवाज उठाई है, उससे

देश के प्रधानमंत्री डर गए, प्रधान मंत्री, मोदी जी डर गए हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करना चालू किया, 08 जून, 2015 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स भेजकर...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पैरा मिलिट्री फोर्से भेजकर और दिल्ली की एंटी क्रप्शन ब्रांच जो कि 40 साल से दिल्ली सरकार के अंडर में थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसमें आश्चर्य नहीं हुआ। मोदी जी का तो इतिहास ही ये है। वो न तो संविधान पर विश्वास करते हैं न किसी चीज पर विश्वास करते हैं। उन्होने एंटी क्रप्शन ब्रांच पर कब्जा कर लिया। जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे है... ये भ्रष्टाचार शीला दीक्षित जी के टाईम में हुआ। पुरानी कांग्रेस के टाईम में भ्रष्टाचार हुआ। ये टेंकर की खरीद फरोख्त को लेकर कोई भ्रष्टाचार है, जो शीला दीक्षित जी के टाईम में भ्रष्टाचार हुआ और सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस और बी.जे.पी. के बीच में कैसा हसबैण्ड–वाईफ का रिलेशनशिप है। पति–पत्नी का रिलेशनशिप है दोनो के बीच में। एक दिन कपिल मिश्रा जी ने ये चिट्ठी लिखी, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। यह चिट्ठी देखकर मैं तो एक दम दंग रह गया! इतना बडा मामला! लेकिन मैं यह सोच रहा था... हमारे पास ए.सी.बी. थी नही। हम क्या करते? हमारे पास ए.सी.बी. थी नही। हम कैसे जांच करते? किससे जांच कराते? हमारे पास एंटी क्रप्शन ब्रांच थी नही। आज मैं यह कहना चाहता हूं इनके पास ए.सी.बी. है, इनके पास सी.बी.आई. भी है, उनके पास पैरा मिलिट्री फोर्स, इनके पास दिल्ली पुलिस है, इनके पास ए.सी.बी. है, इनके पास सारी फोर्सेज हैं। ए.सी.बी. का दफ्तर सामने है शायद।

.....(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां से ये अगर गाड़ी उठाएं, इनको पांच मिनट लगेंगें वहां ए.सी.बी. पहुंचने में। इनका मकसद केवल और केवल भ्रष्टाचार पर राजनीति करना है। इनका कोई इंन्ट्रेस्ट नहीं है भ्रष्टाचार से। इनका मकसद लोगों को पीटना, गुंडागर्दी करना, सदन के अंदर माइक तोड़ना, सदन के अंदर लड़कियों को गालियां देना, ये ही उनका मकसद है। इन से सुना नहीं जाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप बात कैसे कर रहे हैं ? विजेन्द्र जी, पहले सी. एम. को बोलने दीजिए। विजेन्द्र जी, पहले सी.एम. को बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आज मैं इनको चैलेंज करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए विजेन्द्र जी। उनको बोलने दीजिए पूरा। विजेन्द्र जी, बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, मुख्य मंत्री बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए। नहीं, कब गाली दी है ? गाली कब दी है उन्होंने ? नहीं, आपको गुंडा नहीं कहा। गुडांगर्दी कहा है। कल हुई है गुंडागर्दी रामलीला मैदान में। आप बैठिए। अभी बैठिए। आज आपको गुंडा नहीं कहा।

मुख्य मंत्री : कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। इन्होने हमारे विधायकों के खिलाफ कम्पलेंट करी ए.सी.बी. में। तब तो मेरे फैक्ट फाईडिंग

लेने नहीं आए ! इन्होने प्रिमियम बस सर्विस के खिलाफ करी। मेरे से फैक्ट फाईडिंग लेने नहीं आए। अब ये फैक्ट फाईडिंग वगैरह का बहाना क्यों बना रहे हैं? सेटिंग कर रखी है इन्होंने शाली दीक्षित से। आज मैं चैलेज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक महीने के लिए ए.सी.बी. दे दो, एक महीने के लिए ए.सी.बी. वापिस दे दो।

...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आज अगर एक महीने के लिए ए.सी.बी. मिल जाए, इसकी भी जांच कर लेगें और इनकी धर्मपत्नी की भी जांच कर लेगें। अगर एक महीने में विजेन्द्र गुप्ता जी के धर्मपत्नी जेल न चली जाए तो मेरा नाम बदल देना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजेन्द्र जी, मैं बार–बार कह रहा हूं आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बैठिए। मैं खडा हूं।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता सदन में अपने आसन (डेस्क) पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः सदस्यों से प्रार्थना है... राखी जी, आप बैठ जाइए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठ जाइए प्लीज। मुझे लग रहा है कि विजेन्द्र जी, दिल्ली नगर निगम पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।

वे नहीं चाहते कि दिल्ली नगर निगम पर चर्चा हो और वे समय खराब कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाईडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया है, उसकी रिपोर्ट कल आप मुझे दे देना। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाईडिंग रिपोर्ट दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो पेन्शन का घोटाला किया है, उसकी रिपोर्ट आप हमें दे देना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन जी, बैठिए। अनिल बाजपेयी जी, कोई बात नहीं। खड़े रहने दो। बैठिए, बैठिए प्लीज। मैं सदन से प्रार्थना कर रहा हूँ जरा शांत हो जाएं। विजेन्द्र जी, एक सैकेंड, बैठ जाइए। सुरेन्द्र जी प्लीज। ये सदन पिछले सवा साल में माइक तोडने पर शर्मसार हुआ, अपनी महिला सदस्या के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर शर्मसार हुआ और मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में कोई एम.पी. या विधायक इस तरह से बैंच पर चढ कर खड़ा हुआ होगा, मुझे ध्यान नहीं है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती! इससे बडी शर्म की बात नहीं हो सकती! आप सदन का सारा समय हाईजैक करते हैं। मैक्सिमम समय और अब आगे से..... सुरेन्द्र जी बैठिए प्लीज। जैसा मैने अभी कहा और विजेन्द्र जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस ढंग से बैंच पर खड़े होना, ये संसदीय परम्पराओं का बहुत बड़ा अपमान है। और मुझे ध्यान नहीं, कभी कोई विधायक। नेता प्रतिपक्ष है आप तो। इस ढंग से बैंच पर खडा हुआ हो। बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : चलो, अब शांत हो जाएं। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रार्थना करता हूं कि वो प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुश्री राखी बिड़ला जो इस सदन की सदस्य है, को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीप सिंह जी। माननीय मुख्य सचेतक, प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुश्री राखी बिड़ला जो इस सदन की सदस्य हैं, को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : अध्यक्ष जी, मैं श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुश्री राखी बिड़ला जो इस सदन की सदस्य हैं, को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अमानतुल्लाह खान जी प्रस्ताव रखेगें।

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सुश्री राखी बिड़ला जो इस सदन की सदस्य हैं, को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री अमानतुल्लाह खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत और श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव कि सुश्री राखी बिड़ला जो इस सदन की सदस्य है, को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए;

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है वे ना कहें ;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

चूंकि पहला प्रस्ताव पास हो गया है इसलिए नियमानुसार अन्य प्रस्ताव को लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः सुश्री राखी बिड़ला सर्वसम्मति से सदन की उपाध्यक्ष निवार्चित हो गई हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सुश्री राखी बिड़ला को इस सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आज जन्म दिन के शुभ अवसर पर उपाध्यक्ष निर्वाचित होना वास्तव में सुश्री राखी बिड़ला जी के जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है जो अपने जीवन में उनको हमेशा याद रहेगा। साधारण दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुश्री राखी ने 26 साल की उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शानदार शुरूआत की और कई रिकार्ड कायम किए। दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार से जनसंचार विषय में एम.ए. और दिल्ली के एक स्थानीय टी.वी. चैनल में बतौर रिपोर्टर अपना कैरियर शुरू किया।

सुश्री राखी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी खास पहचान आसानी से बना सकती थी लेकिन जन सेवा की प्रबल इच्छा के कारण वे राजनीति में आ

गई। अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए सुश्री राखी कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही हैं। 2013 में पहली बार दिल्ली विधान सभा की सदस्य चुनी गईं। इसके बाद दिल्ली की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव भी आपको हासिल हुआ। महिला व बाल विकास मंत्री पद पर रहते हुए, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी अधीनस्थ विभागों की कार्यप्रणाली दुरूस्त करने का बीड़ा उठाया। ये विधान सभा की महिला और बाल विकास समिति की भी अध्यक्ष रही हैं। विधान सभा की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से भाग लेती हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण चर्चा में योगदान देती हैं। मुझे आशा है कि विधान सभा की उपाध्यक्ष पद पर आसीन हो कर सुश्री राखी स्वस्थ संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए इस सदन के संचालन में सहयोग देंगी और निष्पक्षता पूर्वक उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगी।

मैं विधान सभा की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संदन के संचालन में दिए गए सहयोग के प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सम्यक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विभिन्न अवसरों पर सदन के अन्दर तथा बाहर पूर्ण सहयोग दिया और अपने शालीन व्यक्तिव और कुशल कार्य प्रणाली से उपाध्यक्ष की पद की गरिमा में वृद्धि की। अब राखी बिड़ला जी सदन का धन्यवाद करेंगी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से तमाम चुने हुए सम्मानित सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने वोट देकर आज उपाध्यक्ष के लिए मुझे चुना। आप सभी लोगों का बहुत–बहुत धन्यवाद। हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्य

मंत्री साहब का कि आज उन्होंने मेरे जन्म दिवस के मौके पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे विश्वास के साथ सौंपी है और मैं पूरे सदन को इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि जिस प्रकास से एक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है– निष्पक्षता के साथ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन को चलाना, उस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से पूरे जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगी और पुनः सदस्यों से बस यही विनती करूंगी कि सदन का गौरव, सदन की गरिमा बनाए रखें। विपक्ष के साथी जो कुछ भी करें, हमें अपना टैम्पर नहीं खोना है। हम लोगों अपनी सीमाओं में रहना हैं। पुनः पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और माननीय सी.एम. और डिप्टी सी. एम. का बहुत–बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और उम्मीद करती हूं कि आगे भी जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा, पूरी ईमानदारी और पूरे नियमावली के साथ इसको पूर्ण करूँगी और अध्यक्ष जी का इस निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले महौल था, मुझे लग रहा था कि चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने ही माहौल को सुखद बनाया, उसके लिए भी बहुत–बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन के तमाम साथियों का बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

बधाई प्रस्ताव (नियमः114)

अध्यक्ष महोदयः नियम 114 के अन्तर्गत श्री जरनैल सिंह जी की ओर से मुझे एक धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन): दिल्ली के अन्दर पंजाबी भाषा को एक तरह से बेगानापन महसूस हो रहा था। बड़े लंबे समय की लड़ाई के बाद दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन असल में वास्तविकता में वो दर्जा नहीं दिया। स्कूलों में टीचर नहीं थे। जिस तरह से उर्दू भाषा पर जोर दिया गया कि शायद मुस्लमानों की भाषा है। पंजाबी पर जोर दिया कि शायद सिक्खों की भाषा है। लेकिन दिल्ली के अन्दर सिख बिरादरी से ज्यादा पंजाबी बोलने वाले शायद आप भी बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी बोलने वाले बहुत लोग हैं। स्कूलों में टीचर नहीं थे तो दिल्ली सरकार ने यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि दिल्ली के हर स्कूल के अन्दर पंजाबी के टीचर रखे जाएंगे। इसके अलावा इन टीचर्स की तनख्वाहें जो कोई 4 हजार थी कोई 6 हजार थी कोई 8 हजार थी, उसको भी बढ़ाने का फैसला किया और तीसरी, जो सबसे बड़ी बात हक, सच और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक महान योद्धा बाबा बन्दा सिंह बहादुर, गुरू गोबिन्द सिंह जी के बच्चों को जिन्होंने शहीद किया था– 5 साल के, 7 साल के जिन्हें दीवारों में चुन दिया था उनके साथ ईंट की ईंट खड़काने वाले सरहिन्द के सूबेदार को, वजीर खान को सजा देने वाले और सच का राज कायम करने वाले बाबा बन्दा सिंह बहादुर जिनको तीन सौ साल पहले दिल्ली की एक सरकार ने, दिल्ली के तख्त ने शहीद कर दिया था। तीन सौ साल बाद दिल्ली की एक सरकार ने उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए बारापुला के उस फ्लाइओवर का नाम बाबा बन्दा सिंह बहादुर के नाम पर रखने का फैसला किया। मैं इसके लिए अरविन्द केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का जिन्होंने खासकर पंजाबी भाषाा के टीचर रखने के लिए,

उनकी लैंग्वेज के, उनकी सैलरीज बढ़ाने के लिए जो ये फैसला किया है, मैं एक धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि ये सदन इसको सर्वसम्मति से पास करेगा।

अध्यक्ष महोदयः ये प्रस्ताव सदन के सामने है। मैं समझ रहा हूं कि इसमें कोई वो भी नहीं है। सभी इस पर अपना खुशी प्रकट करेंगे। सदन के सामने... पारित माना जाए? बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष महोदय, उर्दू का भी उसमें जिक्र आया है कि उर्दू की बहुत सालों से... उर्दू टीचर के लिए एक मांग हो रही थी, तो उसमें दिल्ली सरकार ने सारे स्कूलों में उर्दू टीचर्स की बहाली का फैसला किया। ये एक बड़ा कदम है जो उर्दू टीचर्स की जरूरत थी बहुत सालों से, पिछले 25–30 सालों से भर्ती नहीं हुई तो उसमे तमाम दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें एक–एक टीचर देने का और जो उर्दू मीडियम के टीचर्स है, तकरीबन 15 सौ उर्दू टीचर्स देने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है तो मैं उनके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का कि जो ये फैसला लिया है, उसके लिए हम भी सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदयः अमानतुल्लाह जी के प्रस्ताव को और जरनैल सिंह जी के प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए और दोनों प्रस्तावों...

जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** सर, आधा मिनट लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आधा मिनट लेना चाहता हूं। मेरा दिल कर रहा है कि आज इस ऐतिहासिक वक्त पे जब यह फैसला हुआ है, मैं दो लफ्ज जो है, दो लाइनें

पंजाबी में जरूर बोल दूं। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी दा ते उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी दा, इस ऐतिहासिक फैसले दे लई जो पंजाबी बोलन में समय तो देश तो दूनिया दे विच ऐ मांग कर हैं सी पंजाब, पंजाबी नू एक बदाया जाएं ते नाल ही बाबा बन्दा सिंह बहादुर वरगै उस महान जोदे ओ महान जरनैल दी शहादत नू प्रणाम किता जाए। ऐ इस दिल्ली दी सरकार ने तीन सौ साल बाद ऐस मननू स्वीकार किता, ऐदे लिए मैं दिल दी गहराई तेनु धन्यवाद करदा।

अध्यक्ष महोदयः हुन मैं मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मंख्यमंत्री जी नू प्रार्थना करण लग्या कि इस प्रस्ताव ते अपने विचार रखणगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाबी में थोड़ा गरीब हूं और मैं गरीबी को लेकर अपना हाल अभिव्यक्त कर सकता हूं कि पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम भी किया है और यह भी देखने कि कोशिश की कि कहां त्रुटियां रह गई, कहां चीजों को समझने में गलतियां रह गई। ये जो सामाजिक मान्यता है कि... एक पारंपरिक मान्यता रही कि पंजाब में पंजाबियों की, अब सरदारों की भाषा रहेगी और उर्दू मुसलमानों की भाषा रहेगी। शायद उसी मान्यता से प्रेरित होकर या उसी से ड्रिवन हो के हमारी पोलिसी मेकर्स ने कुछ पोलिसी बनाई होंगी और इसलिए जहां–जहां दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम भाई अधिक रहते हैं, वहां के स्कूलों में उर्दू टीचर्स की व्यवस्था कर दी गई और जहां सिक्ख भाई अधिक रहते हैं, वहां पंजाबी टीचर्स की व्यवस्था कर दी गई। मैं अलग–अलग स्कूलस में जाता था, वहां लोगों से

पूछता था कि यहां पंजाबी क्यों नहीं पढ़ते, उर्दू क्यों नहीं पढ़ते? बोले जी, ''यहां बच्चे ओपशन्स नहीं लेते।'' हमारे जरनैल भाई से... और दोनों भाइयों से बात हुई और भी तमाम साथियों से बीच–बीच में अपने विधायक साथियों से बात हुई। अवतार सिंह जी से भी बात हुई कि इसका क्या समाधान निकाला जाए क्योंकि इन–प्रिंसिपल ये सरकार और हम सब साथी चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सब यकीन करते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है और पंजाबी सिर्फ सिक्खों की भाषा नहीं है। ये तो आम हिन्दुस्तान की भाषाएं हैं। आम हिन्दुस्तानी अपने घरों में इन सब में बात करता रहा है। आज हम अलग–अलग धर्म जातियों के लोग यहां बैठे हैं, एक तरह से पूरे हिन्दुस्तान के लोग बैठे हैं और हम सब जानते हैं कि हममें से किसी की भी भाषा शुद्ध परिमार्जित हिन्दी भी नहीं है। हम सब अपनी आम बोल चाल की भाषा में आधे शब्द उर्दू और पंजाबी से लेकर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घरों में। तो ऐसे में मुझे यह जरूरत महसूस हुई कि इसको इस दायरे से निकाला जाए कि बच्चे चूज करना चाहेंगे, तो उनको पढ़ाई जाएगी। क्योंकि किसी भी स्कूल में सामान्य प्रक्रिया यह होती है कि पैरेंट्स अपना सब्जेक्ट अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि क्या पढ़ाएं, देखते हैं कि क्या–क्या सब्जेक्ट यहां ऐवलेबल हैं। जो–जो ऐवलेबल है, उनमें से पढ़ा देते हैं। तो हमने यह निर्णय लिया कि आप उपलब्ध तो सब जगह कराइए। जहां भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे, वहां पढ़ेंगे। क्योंकि टीचर नहीं होने पे कोई बच्चा क्यों चूज करना चाहेगा ? जिस स्कूल में उर्दू का टीचर नहीं है, वहां के बच्चे अगर उर्दू पढ़ना भी चाहेंगे तो उनको पहले से पता है। यहां तो उर्दू का टीचर ही नहीं है, यहॉ उर्दू

सिलेक्ट करने का क्या फायदा? जहां पंजाबी का टीचर नहीं है, वहां बच्चे सोचेंगे पंजाबी सिलेक्ट करने का क्या फायदा? यहां तो पंजाबी का टीचर ही नहीं है तो वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाते थे। अब उसको एक चूज ओपशन ही नहीं ले पाते थे। इसलिए हमने यह तय किया कि पूरी तरह से दिल्ली के हर एक सरकारी स्कूल में पंजाबी और उर्दू के टीचर, योग्य टीचर्स, बहुत टैलेंटेड टीचर्स हम स्क्रीनिंग करेंगे उनकी... अच्छी सैलरी पर... कोई रैजगारी वाली सैलरी पर नहीं कि मतलब ऐसे ही फॉरमेल्टी के रूप में टीचर्स भर्ती कर लिए जाएं। अच्छी क्वॉलिटी के टीचर्स वहां तैनात किए जाएंगे। ताकि हमारे समाज में पंजाबी और उर्दू के पढ़ने–पढ़ाने का, सीखने–सिखाने का ऑपशंस रहे। पुराने हिन्दी, उर्दू साहित्य और उनकी परंपराओं को लोग उसी रूप में समझा सकें। उसके साहित्य का घरों में अध्ययन हो सके। इसलिए यह फैसला लिया गया है।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री जरनैल सिंह जी, तिलक नगर। बहुत कम समय है।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) **:** धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो दिल्ली की दूसरी लैंग्वेज पंजाबी के सपोर्ट के लिए जो दिल्ली सरकार की तरफ से काम हुए, चाहे हर स्कूल में एक पंजाबी टीचर देना... यह बहुत बड़ा काम था। पिछलों दिनों मैंने एक सवाल उठाया था कि कुछ बच्चे पंजाबी पढ़ना भी चाहते हैं पर वहां टीचर नहीं होते, तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक काम है। जेदा पंजाबी दे टीचरा दी सैलरी का इन्क्रीमेंट होया, तुसी बन्दा 2800 सौ रुपये, 3200 सौ रुपये दी सैलरी पर आज तक

काम कर दीया सी। ये अपणे आप चे बड़ा वड्डा काम ते नाल ही नाल बारापुला का नाम बाबा बन्दा सिंह बाहदुर सेतु रखा गया है। ओदे वास्ते मैं सारे पंजाबियां वलों, सारे सिक्खों वलों, दिल्ली सरकार दा धन्यवाद करदा ते एक इंफोरमेशन देना चानदा कि दिल्ली विच पंजाबी अकेदमी हैं, जिदा वाइस चेयरमैन दी सेवा मैनू मिली है, तो ओदे चेयरमैन आप मुख्यमंत्री साहब ने आप सवेरे उठ के दो अखबारा पंजाबी दे पढ़ रहेने, सारेयां दे वास्ते एक पंजाबी बोलन वास्ते, पंजाबी सूनलेण वास्ते बड़ी खुशी दी गल है। ते एक बार सारे पंजाबियां तो पंजाबी बोलन वालियां नो दिल्ली सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करदा हॉ। ते इस प्रस्ताव दा पुरजोर समर्थन करदा हां।

अध्यक्ष महोदयः अवतार जी।

सरदार अवतार कालकाजीः बहुत धन्यवाद करदा हां साडे सी.एम. अरविन्द केजरीवाल दा और मनीष सिसोदिया जी दा और साडे सिक्ख एमएलए ने असी सारेयां ने मिलके विनती कित्ती की इन सारेयां नू परवान भी कित्ता और शिक्षा दे मार्ग विच ऐनी चड़दी कलां दे जा रहा है न सच्चे बादशाह से अरदास करदे हां कि जो देश दी सेवा कर रहें ने ऐदे विच हमेशा चड़दी कलां विच रहन, बहुत–बहुत पूरे देश दा भला कर दे आ दिल्ली वाले दा धन्यवाद करदे हॉ जिन्हाने मतलब पंजाबी नू इन्हा साथ दित्ता होया और पंजाबी चल दी दिल्ली ते विच ओदे वास्ते आपा बहुत–बहुत धन्यवाद कर दें हॉ। जय हिन्द, जय भारत।

सुश्री अल्का लाम्बाः सर, पंजाबी जेड़ी है, वो सिक्खा दी ही भाषा नहीं है क्योंकि मैं खुद नॉन सिख पंजाबी आ। लेकिन मैंनू गर्व हैगा जिन्हें

साडे सिख वीरानू हेगा और ऐ साबित कित्ता होगा कि पंजाबी वास्ते खाली सिक्खा दी नहीं है, वो सारियां दी हैगी। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारतीः आज जैड़ी प्रपोजल आई है ऐ धन्यवाद करदा मैं नॉन सिक्ख, नॉन पंजाबी हेगा। ये पंजाबी भाषा जेड़ी है, सब नू आंदी करीब करीब। सब नू बधाइयां माननीय मुख्यमंत्री नू बधाइयां लख–लख बधाइयां। ए बड़ी थोड़ी बहुत तो सब ने आंदी है पंजाबी मैनू फूलैंट आंदी है। बहुत बहुत बधाइयां जी।

अध्यक्ष महोदयः चलिए अब, श्री इमरान जी, मंत्री जी।

श्री इमरान हुसैन (खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री): मैं माननीय मंख्यमंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज के लिए जो टीचर्स की नियुक्ति के लिए किया है और जो अब से पहले जो भी सरकार आई, उन्होंने पंजाबी और उर्दू के लिए हमेशा भेद–भाव किया है इसके लिए में बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री जगदीप सिंहः मैं सर, सिर्फ दो गल्लां करना चाहूंगा तुहाड़ी परमिशन नाल कि बिल्कुल अल्का लाम्बा ने ठीक कहा हेगा कि पंजाबी खाली सिक्खा दी भाषा नहीं हेगी। ऐ कबीर दास जी दे टाईम ते जेड़ी उना दी बाणी जेड़ी उस वेल्ले निकली हेगी है। ओ तुस्सी अगर देखो तो पंजाबी भाषा विच लिखी हुई हेगी है उसनू गुरू नानक साहब ने अपना और पूरे देश, विदेश विच जाके उदा प्रचार कित्ता। हां, मिट्ठी बोली हेगी, इसलिए मिट्ठा ज्यादा खांदे ने सिख मिट्ठा ज्यादा खांदे है ना। इना ने ज्यादा अपना

लित्ती। ठीक है जी? लेकिन पंजाबी बोली सब दी सांजी बोली हेगी ऐ। ऐ सांझी वालता दे घर हेगा और सारे पराहवा नू उर्दू वास्ते भी जो हेगा, बहुत–बहुत धन्यवाद, सरकार दा एक बहुत ही सफल स्टेप हेगा जो लित्ता सी सरकार ने। अस्सी पूरी सरकार साडे मुख्यमंत्री, साडे उप मुख्यमंत्री ते अपने सारे विधायका नू बहुत–बहुत बधाई ऐ दे वास्ते।

अध्यक्ष महोदयः मदन जी हो गया, अब हो गया।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद, उप मंख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि मेरी बेटी ने पंजाबी सीखी। वो स्कूल में पंजाबी पढ़ी और कई बार मुझसे भी कहती थी कि पापा ये भाषा बहुत स्वीट भी है और सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में बोलते है। इस भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। अगर मेरे जमाने में भी शायद पंजाबी को इतना प्रोत्साहन किसी सी.एम. ने दिया होता तो हो सकता है, हम भी पढ़ लिए होते। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का अब मेरी बेटी को बड़ा गर्व होता है। इसलिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः हो गया। जगदीप जी हो गया बड़ा लंबा। गल सुणो।

श्री जरनैल सिंहः मैं सारे सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली पंजाबियों की तरफ से पंजाबी भाषा सिखाने की स्पेशल क्लासेज दी जा रही हैं, जो भी साथी सीखना चाहते हैं, आप सब कुछ घण्टे में ही सीख सकते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब यह प्रस्ताव अब सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें ;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब मैं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुश्री राखी बिड़ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन तक आएं और आसन ग्रहण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुईं।

विशेष उल्लेख (नियम–280 के अंतर्गत)

उपाध्यक्ष महोदयाः अब रूल 280 के अन्तर्गत चर्चा का समय शुरू हो गया है। श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद उपाध्यक्षा जी, आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी विधान सभा के वार्ड नं0 241 में एक खेड़ा गांव है, जहां लगभग अब से 8 साल पहले सीवर लाईन डल गई थी लेकिन इसी बीच एस.एस.बी.एल. का एक नाला जिसका निर्माण एम. सी.डी. ने किया, उन्होंने उस लाईन को इस ओर कनेक्शन भी तब तक नहीं दिए थे, वो लाईन चालू भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले नाले

का निर्माण करके एम.सी.डी. ने उस नाले को बीच से तोड़ दिया, उस लाईन को तोड़ दिया जो सीवर लाईन थी और उस लाईन को जोड़ने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी लगातार एम.सी.डी. से परमिशन मांगे रहे हैं। लेकिन एम.सी.डी. उसको परमिशन नहीं दे रही है। यहां तक कि मैंने स्वयं कमिश्नर साहब के यहां अपने साथ चीफ इंजीनियर, दिल्ली जल बोर्ड, मिस्टर मनचन्दा को साथ लेकर और एम.सी.डी. कमीश्नर के पास इंजीनियर चीफ के साथ मीटिंग ली, उसके बाद अपने आप ही कनेक्शन भी कराया। लेकिन बड़े दुख की बात है आज तक भी एम.सी.डी. उस सीवर लाईन को जोड़ने की, दिल्ली जल बोर्ड को परमिशन नहीं दे रही है। जिसकी वजह से खेड़ा गांव के ग्राम वासी मजबूरन उस नाली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उस नाली में गंदगी डालने की वजह से खेड़ा गांव के ग्राम वासियों का एम.सी.डी. चालान भी कर रही है। न तो उस सीवर लाईन को जोड़ने दे रही है और न ही उस नाली को यूज करने दे रही है।

उपाध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एम. सी.डी. को निर्देशित किया जाए कि वो उस सीवर लाईन को जोड़ दे ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः श्री संजीव झा जी। चौ. फतेह सिंह जी।

चौ0 फतेह सिंहः धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली के अन्दर चल रहे मोटर ड्राइविंग स्कूलों की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1996 में दिल्ली के अन्दर डी.एस.आई.आर. आया और उसे लोनी रोड पर

परिवहन विभाग में अपनी मान्यता देते हुए साथ ही अरबों रुपये की जमीन केवल 125 रुपये प्रतिमाह के किराये पर दी। परन्तु डी.एस.आई.आर. व परिवहन विभाग के अधिकारियों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सभी ड्राइविंग स्कूलों का नवीनीकरण 2013 से रोक रखा है जिसके कारण लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो रोजमर्रा की डी.एस.आई.आर. के तहत ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को तीस से चालीस किलोमीटर की यात्रा करके दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, और भी जो अस्थाई लाइसेंस डी.एस.आई.आर. के तहत दिए जाते हैं उनकी अवधि छः माह होती है जिसके कारण से वो समय न मिलने के कारण उनके लाइसेंस एक तरह से स्थगित हो जाते हैं और जो डी.एस.आई.आर. के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वो वंचित रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, डी.एस.आई.आर. को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये का अनुदान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है लेकिन फिर भी ये डी.एस.आई.आर. पूर्ण रूप से लोगों को सुविधा देने में अक्षम साबित हुई है। मेरा यह मानना है इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिया जा चुका है कि ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो छोटे–छोटे अपने ट्रेनिंग स्कूल्स है, उनको नवीनीकरण की इजाजत दी जाए। जिससे डी.एस.आई.आर. से कहीं अधिक उसे दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग कम मकैनिक की भी मान्यता भी दी हुई है और दिल्ली सरकार, भारत सरकार के एन. सी.वी.टी ट्रेनिंग के स्तर को उंचा बनाने के लिए पूरे भारत में अपने स्कूल खोलने के लिए एग्रीमेंट किया है जिसकी ब्रांच इंडिया और अमेरिका में भी

है। दिल्ली में ट्रेनिंग स्कूल से लोग ट्रेनिंग लेते हैं ताकि संस्था के माध्यम से जो प्रमाण पत्र मिलता है, उसके माध्यम से वो कहीं छोटी–मोटी नौकरी कर सकें और अपना रोजगार चला सकें।

.उपाध्यक्ष महोदया, अगर परिवहन विभाग इस पर गौर करे दिल्ली के अन्दर अनेकों प्रकार की समस्याओं से जो गरीब लोग रोज अथोरिटी में चक्कर लगाते रहते हैं; उनको निजात मिल सकेगी। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई और जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है इसके बाद हम सब लोग साथी मिलें।

महोदया, आज जो प्रश्न मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, ये एन. डी.पी.एल. के जो हेल्पलाइन नम्बर दिए गए है, जिसमें बिजली की शिकायत सुनी जाती है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि रात में 90 परसेंट कॉल ड्राप होती हैं और रात में जो भी लाइट जाती है तो कोई सूचना नहीं मिलती और अगर वो सुनते भी हैं तो वो अपनी कॉल को होल्ड पर डाल देते हैं और वो होल्ड पर चला जाता है, इससे लोगों के अननेससरी पैसे चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पर सुनवाई ठीक से नहीं होती। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि एक बार डिटेल आ जाए कि रात में कॉल ड्राप की कितनी शिकायतें आती है और उन में से कितनों का निपटारा होता है। चूंकि हमारे इलाके में बिजली जाती है और ये सुनवाई नहीं होती है रात को दो बजे कोई मेरे पास फोन

करे तो मैं क्या बताऊं कि बिजली क्यूं गई और कब आयेगी, तो रात में कम से कम विशेषतयाः इसकी प्रॉपर सुनवाई हो और उस पर कार्रवाई हो, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम तो आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं और दो खुशी के मौके हैं – एक आपका जन्मदिवस है, दूसरा आज आप इस गरिमामयी पद पर विराजमान हुई है, उसके लिए भी मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से बहुत–बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको मैं देता हूं।

महोदया, आज नियम – 280 में दिल्ली सरकार के द्वारा विज्ञापनों का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी ओर ध्यानाकर्षित करने के लिए मैं वक्तव्य यहां पर दे रहा हूं। अभी दो दिन पहले कम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। ये वही सी.ए.जी. है, जिसको मुख्यमंत्री जी खुद बिजली की कंपनियों के जांच के लिए बोलकर आए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इनका सी.ए.जी. में तो जरूर ही विश्वास होगा। सी.ए.जी. ने कहा है कि साढ़े अठारह करोड़ रूपये का एक ही दिन में सिर्फ प्रिन्ट मीडिया पर खर्चा किया गया है और अंग्रेजी के अखबारों में हिन्दी की एडवर्टाइजमेंट दिए गए। इसके साथ–साथ सी.ए.जी. ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से अगर कंपेरिजन किया जाए तो 2015–16 में जो विज्ञापन पर खर्च होने वाली रकम वो एक गुणा, दो गुणा, चार गुणा नहीं है बल्कि 20 गुणा 15 गुणा है लगभग जो मैं गुणा में बता रहा हूं, ये अनैतिकता की

प्राकाष्ठा है एक आर.टी.आई. के जवाब में कहा गया कि सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, उडीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और दूर–दराज के राज्यों में जिनका दिल्ली में ऑड–इवन से कोई लेना–देना नहीं है, उसके भी ऐड वहां पर देकर के दिल्ली की जनता की खून–पसीने की कमाई को बर्बाद किया गया। आज अभी इस सदन में बात हो रही थी –ये एडवर्टाइजेशन पहले ही पंजाब के अखबारों में दे दिया गया कि पंजाबी शिक्षक लगाए जाएंगे, वेतन बढ़ाया जाएगा और आज के इस सदन में कोई प्रस्ताव नहीं था! आप मजाक कर रहे हैं उन अध्यापकों के साथ। उनके साथ आप उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो गरीब अध्यापकों के लिए किन्तु...

उपाध्यक्ष महोदयाः गुप्ता जी, जो आपने लिखकर दिया है, आप उससे हट रहे हैं। आपने जो लिखकर दिया है, उसको ऐज इट इज पढ़िए। ये 280 है, ये चर्चा का विषय नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जो मैंने लिखकर दिया है, मैं वही बोल रहा हूं। आप मेरी भावनाओं को समझो।

उपाध्यक्ष महोदयाः मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये कैसा एडवटाईजमेंट है? ये एक टीचर को... हमारे को पैसा नहीं दिया, टीचर बाहर भूख–हड़ताल पर बैठे है। वो मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर 17000 टीचर बेचारे इधर–उधर...

उपाध्यक्ष महोदयाः गुप्ता जी जो आपने 280 में दिया है, आप उस पर बात कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के विशुद्ध रूप से राजनीति! मैं समझता हूं कि राजनीति भी शरमा जाएगी आपकी इस तरह की हरकतों से। मुझे समझ नहीं आता आप पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखकर टीचर के साथ धोखा कर रहे हैं और भाषाओं में फर्क कर रहे है आप सब। मैं तो कहूंगा हर भाषा को जिसको दिल्ली सरकार ने रिकॉगनाइज किया हुआ है, सबकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सबको हर स्कूल में लगाया जाना चाहिए फिर उर्दू का टीचर 10 स्कूल में क्यों लगेगा और पंजाबी का टीचर उर्दू स्कूल में क्यों लगेगा? फिर सब जगह लगने चाहिए। तो ये सारी स्थिति है। ये जो स्थिति है, ये गुमराह करने वाली... ना कोई योजना, ना कोई तैयारी, ना किसी को मालूम किससे पढ़ाए जायेंगे, ना ये मालूम कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, बढ़ा दी, लगा दिए करोड़ों रूपये एडवर्टाइजमेंट पर। आप खर्च किए जा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः बहुत–बहुत धन्यवाद ज्यादा नहीं बुलवाया आपने।

श्री मनीष सिसोदिया (उप मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदया, नियम 280 के तहत माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है, मैं समझता हूं इस पर... क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो जिस पार्टी से बिलॉग करते है, मोदी जी की पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। वो उससे ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए उनको 'जुमला' में यकीन है। इसलिए जुमले की बात कर लेते हैं। दस लाख के सूट की बात कर लेते हैं। लेकिन जब जनता की बात आती है तो कम्युनिकेशन जनता के साथ कितना जरूरी है, इसकी

अब उनसे क्या बात करें ? लेकिन कुछ तथ्य रखें है। मैं सिर्फ सदन का ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है सरकार को बदनाम करने की इनकी पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और पूरा प्रचारित किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 526 करोड़ रूपये... 500 करोड़ रूपये के विज्ञापन फूंक दिए बहुत बदनाम किया जा रहा है। पहले तो मैं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सरकार ने 75 करोड़ रूपये से भी कम विज्ञापन पर खर्च किए थे। ये लगातार झूठ बोला जा रहा है और झूठे जुमले उछाल–उछाल के जब मुझे ये पता चला कि सी.ए.जी. की ऑडिट हो रही है इस विज्ञापन को लेके, बहुत संतुष्टि हुई दिल को। मुझे पूरा विश्वास है कि सी.ए.जी. से ज्यादा बढ़िया ऑडिट कोई नहीं कर सकता और दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने कोई नहीं रख सकता। इसीलिए मैं खुद... हालांकि जिस तरह के सवाल पूछे गए, वहां जिस तरह के मुद्दे उठाए गए सीएजी के ऑडिट में, उसमें कुछ एजेंडा लग रहा था मेरे को। उसमें पूछ रहे थे, ''आप अंग्रेजी के अखबारों में हिन्दी का विज्ञापन क्यों दे रहे हैं? उसमें 'आप की सरकार' क्यों लिख रहे हैं ?'' उसमें ऐसी–ऐसी चीजें पूछ रहे थे। उसमें... वो परेशान करते रहे हम काम करते रहे, मतलब परेशान करते रहे का मतलब मोदी जी है ? जैसे सी.ए.जी. को भी पता है कि परेशान कौन कर रहा है। उसमें पूछा गया, उसमें लिखा गया है उसकी लाइन में। ये बात भी संज्ञान में... मुझे लगता है कि रिपोर्ट विजेन्द्र गुप्ता जी ने पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा पर उनका ध्यान नहीं गया होगा उस पर। उस पर लिखा है कि ये जो आपने विज्ञापन दिया कि वो

परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, इसमें परेशान कौन कर रहा है ? क्या आप मोदी जी की ओर इशारा कर रहे हैं , मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ? तो सीएजी को भी पता है कि परेशान मोदी जी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार काम कर रही है, परेशान मोदी जी कर रहे हैं। ये सी.ए.जी. को भी पता है। ये भी ऑडिट में सामने आने वाला है। ये ऑडिट रिपोर्ट खराब है, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। खैर! 75 करोड़ रूपये का पहले तो ये ... दूसरी बात ये रिपोर्ट क्योंकि ठीक से पढ़ी नहीं होगी, 18 करोड़ रूपये, जिसका जिक्र हो रहा है और अच्छी बात यह है कि सी.ए.जी. हमारे पिछले साल का भी ऑडिट कर रहा है और करंट ईयर का भी बड़े अनप्रिसीडेण्टेड तरीके से, कभी होता नहीं है इस तरीके से कि चालू वित वर्ष का भी ऑडिट हो रहा है... ये अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं। जो रिपोर्ट में इंडिकेटिव बातचीत हुई है, वो सिर्फ साढ़े अठारह करोड़ रूपये की हुई है। अभी तो ऑडिट के क्वेश्चन्स आए हैं। साढ़े अठारह करोड़ रूपये पिछले कुछ महीनों में खर्च किए हैं, एक दिन में खर्च नहीं किए हैं, एक बात। दूसरी बात, उसका जवाब देंगे, हम उसका जवाब भी देंगे सी.ए.जी. को। मैं खुद सी.ए.जी. के पास गया, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, ''जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने विज्ञापन के मामले को लेकर ऑडिट शुरू कर दिया, ये जितने आरोप इधर–उधर लग रहे हैं, सारे शांत हो जाने चाहिए इस ऑडिट के बाद।'' दूसरा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारी सरकार विज्ञापन तो करती है, सारी सरकारें करती है लेकिन साथ–साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में बहुत अलग तरीके से काम कर रही है और हमने बजट भी खूब बढ़ाया है। इस सदन ने

बजट बढ़ा के दिया है। इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है, इतना सब कुछ है... हमने कहा, ''उनका भी ऑडिट कराइए। हम भी देखना चाहते हैं। सरकार में क्योंकि हो सकता है कि कोई चूक हमसे हो रही हो। आप ऑडिट करिए। हम उन सारी चीजों को ठीक करेंगे।'' मैं सदन की अनुमति से इसी सदन में सी.ए.जी. की पिछले वर्ष की रिपोर्ट भी रखूंगा। उसमें जब इनकी सरकार थी, प्रत्यक्ष रूप से... प्रत्यक्ष रूप से ये सरकार चला रहे थे। तो उस वक्त के भी सी.ए.जी. के पैराग्राफ इनको भी रखूंगा मैं सदन के सामने। उन्हें पढ़ रहा था आज बैठकर। लेकिन मैंने सीएजी को एक रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, ''साहब, आप दिल्ली में अपनी खिड़की के बाहर झांककर देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली बैठे है। आपको लगेगा आप हरियाणा में बैठे हुए है ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी खिड़की के बाहर की सरकार हरियाणा सरकार क्योंकि आपको सामने खट्टर साहब का विज्ञापन दिखेगा।'' अब आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे आप हरियाणा में चल रहे हैं। खट्टर साहब के इतने विज्ञापन लगे हुए हैं चारों तरफ। मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर साहब ने कुछ तय किया होगा। हो सकता है, उनको मन हो दिल्ली में अगला चुनाव लड़ने का मुख्यमंत्री के रूप में। हमें क्या दिक्कत है? लड़ो। विजेन्द्र जी की कुर्सी जाए तो हमको क्या दिक्कत है ? वो विजेन्द्र जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट न बनाकर खट्टर साहब को बना दें। अपने को क्या दिक्कत है? मोदी जी को जो करना है करें लेकिन मैंने सी.ए.जी.से रिक्वेस्ट किया। उनसे साहब वो हरियाणा सरकार का भी ऑडिट कर लीजिए ताकि कंपेरेटिव हो जाए। केवल सरकार के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं। इनका भारतीय

जनता पार्टी वालों के मोदी जी की पार्टी वाले के विज्ञापन राजस्थान सरकार के दिल्ली में छपते हैं। इनके मध्य प्रदेश सरकार के छपते हैं, इनके छत्तीसगढ़ सरकार तक के छपते हैं। वो महाराष्ट्र में किसी छोटे से पुल का उद्घाटन हो गया तो दिल्ली में उसका विज्ञापन छपता है मैंने कहा कि उसका भी कंपेरेटिव ऑडिट कर लीजिए। हमें अपने ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ–साथ ये भी तय हो कि बाकी राज्य सरकारें विज्ञापनों में क्या खर्च कर रही है और कैसे कर रही है और कितना पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा पर खर्च कर रही है, कितने में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है और कितना जनता के साथ संवाद पे पैसा खर्च हो रहा है। सारी चीजों का ऑडिट होना चाहिए और उसके बाद ये चीज सामने आए। मैं चुनौती देता हूं, विजेन्द्र गुप्ता जी, आज आप मोदी जी को लाइए सामने, हम बताते हैं कि हम विज्ञापन पर कैसा खर्च कर रहे हैं और वो कैसे खर्च कर रहे हैं। दो हजार करोड़ रूपये मोदी जी की सरकार के दो साल पूरा होने पर खर्च हुए। ऐसी चारों तरफ खबर है, अखबारों में भी छप रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि हमने कैसे 75 करोड़ रूपये का सदुपयोग किया और दो हजार करोड़ रूपये का मोदी जी ने कैसा दुरूपयोग किया। दूध का दूध और पानी का पानी, जिस मैदान में कहें, उस मैदान में आ जाइए। विज्ञापन पत्रकार रहा हूं। लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, विज्ञापन बनाना भी आता है, बनवाना भी आता है और कम्युनिकेशन करना भी आता है। जिस तरह का पैसा बाकी सरकारें विज्ञापनों पर बर्बाद कर रही है, कम्युनिकेशन का आदमी हूं, कम्युनिकेशन करना जानता हूं। हमारी सरकार कम्युनिकेशन करती है जनता से, सार्थक संवाद करती है।

लेकिन खट्टर साहब के विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं, केरल के विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं। हमने सी.ए.जी. को इतना रिक्वेस्ट किया कि साहब, बाकी राज्यों का भी इसी तरह का ऑडिट कर लीजिए और कंपेरेटिव हो जाए। मेरी चुनौती है, हमसे कम पैसा सदुपयोग के साथ में कोई भी सरकार... बी.जे. पी. की कोई सरकार खर्च नहीं करती। मोदी जी खर्च नहीं कर रहे मोदी जी 2–2 हजार करोड़ रूपये विज्ञापन दे रहे हैं। हमारी चुनौती है कि हमसे कम और हमसे ज्यादा कोई सार्थकता में कोई सरकार खर्च नहीं कर रही है और जितनी किफायत से हम खर्च कर रहे हैं। बस, मेरा इस सदन से यही निवेदन है जिसमें माननीय नेता, विपक्ष भी है कि आप बिल्कुल आपके दायित्व में नजर रखें। लेकिन एक तथ्य है, उससे गुमराह न करें। मुझे पता है पूरी साजिश चल रही है। अभी कल जो इस सदन में किया है। मुझे कही से किसी ने बताया कि अगला घोटाला जिस पर एफ.आई. आर. होने वाली है, वो विज्ञापन घोटाला बताया जा रहा है। कल के बाद... कल आप लोगों के यहां की चर्चा के बाद जो मुझे किसी फोन करके बताया कि साहब अगला एफ.आई.आर. एल.जी. के यहां से कहा जा रहा है, बार–बार ये जो विज्ञापन घोटाला हो रहा है, सो कॉल्ड, इस पर जरूर एफ.आई.आर. करो। इस पर देरी क्यों हो रही है ? अब वो एफ.आई.आर. , हो तो कैसे हो? कहा क्या जा रहा है। मैं एक चीज और रख दूं सदन के सामने क्योंकि अब मैंने रखा है, इसका जवाब दे रहा हूं। बड़े शान से कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया ने 500 करोड़ रूपये के विज्ञापन अपने रिश्तेदारों की कंपनी को दे दिए। मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ

ताल ठोक कर कहता हूं, ''मेरे खानदान में कोई विज्ञापन वाला नहीं है।'' लेकिन साजिश की जा रही है, बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि विज्ञापन का घोटाला कर दिया उन्होंने। 75 करोड़ रूपये के खर्चे को 500 करोड़ का खर्चा 18 करोड़ रूपये का खर्चा कुछ महीनों में किया गया, उसको एक दिन में बता रहे हैं। तो इस तरह के तथ्यों को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत न करें और चुनौती के साथ कहता हूं आ जाओ, अपनी सरकारों के साथ में। सबसे कम खर्च कर रहे हैं, सबसे किफायत के साथ कम खर्च कर रहे हैं जिस तरह से जुमलों में, जिस तरह से सूट–बूट में बर्बाद किया जा रहा है, एक पैसा दिल्ली सरकार का बर्बाद नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयाः श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के.बग्गाः उपाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया।

महोदया, मैं आपका ध्यान ई.डी.एम.सी. की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं कष्ष्णा नगर विधानसभा से विधायक हूं। कृष्णा नगर निगम के चारों वार्डों में गंदगी के इतने ढेर लगे हुए है, नाली भरी पड़ी है। इतनी बदबू आ रही है वहां पर कि लोगों का रहना दुश्वार है। ई.डी.एम.सी. को कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। निगम पार्षद तो वाकई में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है बल्कि वो जनता को भड़का रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निगम पार्षद की वो नहीं निभा रहे हैं। वाकई ई.डी.एम.सी., निगम पार्षद न

सड़कें, न नाली, न स्ट्रीट लाइटें कार्य कर रही है इनसे वाकई जनता बहुत परेशान है। महोदया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ई.डी.एम.सी. के कमिश्नर व अधिकारियों को बुलाकर बताएं कि जो निगम पार्षद की ड्यूटी है, उसे पूरा करें जिससे जनता को राहत मिलती है। नही। तो वहां जनता उनको बख्शेगी नहीं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री जगदीश प्रधान जी।

उप मुख्यमंत्री : मेरी सदन के जरिये आपसे विनती है, अध्यक्ष महोदय से विनती है, अध्यक्ष महोदय अपनी कुर्सी पर आसीन हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

उप मुख्यमंत्री : क्योंकि कल भी हम लोगों ने एक चर्चा शुरू की थी, वो भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई थी और आज भी काफी समय इसमें चला गया। अगर यह सदन सहमत हो तो हमें एक वैट से संबंधित बिल भी प्रस्तुत करना है। अगर सदन की कार्यवाही को उस रूप में, सदन में बिल प्रस्तुत करने की भी भरी अनुमति दी जाये। उसके बाद जो चर्चाएं थी, उसकी तरफ भी बढ़ा जाये तो मैं विनम्रता से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि 280 के स्थान पर अगर आगे की कार्यवाही में बिल प्रस्तुत करने को और उन सब को शामिल कर लिया जाये, जो आगे चर्चाएं होनी हैं, उसको शामिल कर लिया जाये, ऐसा मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव आपके सामने है। इसमें बाकी के जो सदस्य 280 में रह गये हैं, उसको पढ़ा माना जायेगा।

उसका उत्तर उनको स्वाभाविक रूप से मिल जायेगा। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे

हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक का पुरःस्थापन

अध्यक्ष महोदयः श्री मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या–3) को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या–3) को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक एक बार पहले भी सदन में रखा जा चुका है, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियाँ ऐसी थीं, हमारे लॉ सेक्रेट्री साहब उस वक्त लगातार छुट्टी पर थे और सदन बुलाना था। जी.एन.सी.टी. एक्ट की क्लॉज यह व्यवस्था देती है कि अगर सदन में कोई विधेयक पास होता है तो केन्द्र सरकार या उपराज्यपाल महोदय उसको बाद में भी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन जब सदन से पास होकर यह विधेयक वहाँ गया था तो उसके बाद उपराज्यपाल महोदय से चर्चा हुई और उनका आग्रह था कि इसको सदन में पास करने से पहले उनकी अनुमति प्राप्त कर ली जाये। उस प्रक्रिया का पालन किया जाये तो उस प्रक्रिया का, उनके आग्रह का सम्मान करते हुए सरकार ने यह तय किया था कि इसको पुनः सदन के सामने लाया जाएगा, उनकी पूर्व अनुमति लेकर। वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उनकी पूर्व अनुमति ले ली गई है इस बार और उसके बाद यह संशोधन विधेयक पुनः सदन में लाया जा रहा है। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों के पुनः स्मरण के लिए थोड़ा सा दो मिनट में यह बता देता हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या किया था। इस पर हमने चर्चा भी की थी, इसके फायदे पर भी चर्चा की थी कि किस तरह से इसमें टैक्स कलैक्शन से लेकर और व्यापारियों के लिए किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से शोषण कम होगा। उनको कई ऑनलाइन सुविधाएँ मिलेंगी। मौटे–मौटे तौर पर इस विधेयक में एक तो जो इम्पोर्ट करने वाले व्यापारी हैं, अभी उनसे जिस वक्त वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, उसी वक्त उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, बाद में लिया जाता है और उसमें काफी हेरा–फेरी

होने की गुंजाइश रहती है। बहुत सारे व्यापारी जनता से टैक्स ले लेते हैं लेकिन उससे वो बच निकलते हैं। सरकार की ट्रेजरी में नहीं देते हैं तो उसको unregistered dealers are importing goods from outside India उनको भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है। दूसरा, जब एक व्यापारी फाइल रिटन करता है तो कहने के नाम पर हमने ई–गवर्ननेंस के नाम पर यह व्यवस्था तो कर दी थी कि हम ऑनलाइन रिटर्न ले लेंगे, लेकिन बाद में व्यापारी को उसकी कॉपी वहां वैट ऑफिस में देना जरूरी होता था। कई बार वो भूल जाते थे और उसकी ई–फाइलिंग को वैलिड नहीं माना जाता था, क्योंकि लॉ में ऐसा प्रावधान था इसलिए संशोधन करके हम यह प्रस्ताव ला रहे हैं कि फिर हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। एक बार अगर किसी ने ई–फाइलिंग कर दी रिटर्न की तो उसको हार्ड कॉपी में लाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, टैक्स डिस्क्रिपेंसीज में जो 10 हजार रुपये की पेनल्टी थी, छोटी–छोटी त्रुटियाँ व्यापारियों से होती हैं, बहुत बार व्यापारी को कानून को लेकर, व्यवस्था को लेकर इतनी सूचनाएं नहीं होती, उस पर 10–10 हजार रुपये की पेनल्टी का प्रावधान था, तो उसमें हमने पहले भी प्रस्तावित किया था। इसमें वही चीजें हैं कि उसमें दस हजार रुपये की जगह एक हजार रुपये की पेनल्टी हमको लगानी चाहिए। दस हजार रुपये की पेनल्टी को रिड्यूस करके एक हजार रुपये पर लाने का था ताकि छोटे व्यापारियों को इससे, छोटी–छोटी गलतियों पर दस हजार रुपये की बड़ी पेनल्टी की प्रताड़ना न झेलनी पड़े। इसके साथ–साथ कुछ एमनेस्टी स्कीम सरकार समय–समय पर ला सके, उसके लिए सरकार को पावर दी गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट की पावर इसमें दे दी गई। साथ–साथ मैंने पिछली बार

भी जिक्र किया था, जब इस बिल को प्रोड्यूस किया था कि प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाने की सरकार शुरूआत करना चाह रही है। सरकार ने प्रायोगिक तौर पर शुरू भी की है, क्योंकि एक व्यापारी के यहां जब कोई कस्टमर कुछ खरीदारी करता है तो टैक्स देकर करता है। वो टैक्स का पैसा जनता से तो ले लिया जाता है, कुछ मामले में यह सामने आया है फिर सरकार को नहीं दिया जाता। व्यापारी को टैक्स नहीं देना, जनता को टैक्स देना है। हमने अभी जो 'बिल बनाओ, ईनाम पाओ' स्कीम लागू की है, उसके तहत् यह चीज बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आई है कि दिल्ली में कई सारी ऐसी प्रेक्टिसेज चल रही हैं, जो करप्ट प्रेक्टिसेज हैं कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में अपने कस्टमर से, मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 100 रुपये भी ले लेंगे और 12 रुपये या 5 रुपये टैक्स के भी ले लेंगे और उसको कलेक्ट करके अपनी जेब में रख लेंगे, फिर देंगे नहीं सरकार को। उसको शाम को डिलिट कर देते हैं, शाम को अपने डेटाबेस से भी उड़ा देते हैं। ऐसी भी प्रेक्टिसेज सामने आई थीं। ऐसे में क्या है कि फिर टैक्स कम होता है या तो सरकारों को टैक्स बढ़ाना पड़ता है या कम में काम चलाना पड़ता है। जनता ने टैक्स दे दिया, उसके बावजूद सरकारी खजाने में टैक्स नहीं पहुँचता। उस टैक्स को ऑनलाइन रखने के लिए जैसे ही वहाँ टैक्स दिया, वैसे ही उसका ऑनलाइन रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध हो जाएगा और कोई भी कस्टमर, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गये, वहाँ आपने बिल लिया, कुछ परचेज किया मार्किट से, वहाँ आपने बिल लिया, उस बिल को आपने जैसे ही लिया, आपके पास उसका टिन नंबर, टैक्स नंबर, बिल नंबर वगैरह सब आ गया

तो वो ऑनलाइन वैट डिपार्टमेंट के हमारी सरकार के डेटा बेस पर, आपने 100 रुपये की परचेज की, उसका डिटेल आ जाएगा। कोई भी कस्टमर अपना डिटेल डालकर चैक भी कर सकता है कि मेरा टैक्स वास्तव में सरकार के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। सरकार के रिकार्ड में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह के डिवाइसेस उनके सेल के साथ में लगाने का अभी संशोधन है तो यह संशोधन विधेयक पुनः इस सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। अगर सदस्यगण चाहेंगे तो इसमें पुनः भी चर्चा की जा सकती है और अन्यथा जैसा सदन की अनुमति होगी, इसको पारित करके उपराज्यपाल महोदय के पास में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : कल जो चर्चा हमने नगर निगम पर बीच में रोकी थी, जरनैल सिंह जी उस वक्त बोल रहे थे। श्री जरनैल सिंह जी, राजौरी गार्डन।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैंने कल भी कहा था. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिये, मेरी बात सुन लीजिए। जब मेरे पास विषय आयेगा, वैसा होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, चूंकि आप वेस्टेड इंट्रेस्ट से, राजनीति दृष्टि से पूरे भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के बाकी मामलों को आप दबाना चाहते हैं, इसलिए हम चर्चा में भाग नहीं लेंगे...(व्यवधान)

(बी.जे.पी. के दोनों माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)

श्री जरनैल सिंह (आर.जी.) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। कल जगदीश प्रधान जी कह रहे थे कि विजेन्द्र गुप्ता जी के कुछ फालतू स्टाफ को हटा दिया गया तो मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ स्टाफ हट जाने से इतने मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो जाते हैं। हम यह कह देते हैं कि आपने हमारे पार्षद पर हमला किया, आपने जगदीप सिंह पर केस कर दिया, आपने जरनैल सिंह पर केस कर दिया, आपने महेंद्र यादव पर केस कर दिया, आपने हमारे विधायकों पर केस कर दिया लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं होते, हमारी और हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन आपका कुछ स्टाफ चला गया तो आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने लगे।

अध्यक्ष जी, अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लागू की गई है, जो कल विषय था, वो पूरा हो गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। प्रधानमंत्री जी इस समय देश, दुनिया में घूम रहे हैं। आप वांशिगटन गये हैं, न्यूयार्क गये हैं। वहां पर सिविक एजेंसीज किस तरह से काम करती है, वहां के नगर निगम किस तरह से काम करते हैं, अगर कम से कम वो सीख कर आ जायें तो इस देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत बेहतर हो जायेगा। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम, ये तीनों बी.जे.पी. के पास है। तीनों के मेयर भा.ज.पा. के हैं। क्या नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दो साल में कभी अपने इन तीन मेयरों को बुला कर कहा कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, आपने उसको क्यों विफल कर दिया ? उसके क्या हालात है,? जो 10 हजार फोटोग्राफ आपके पास

भेजी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके क्या हालात हैं ? अगर नरेन्द्र मोदी जी ने अपने तीनों मेयरों को बुलाकर पूछा होता तो शायद कम से कम जिस दिल्ली के अंदर संसद है, जो एक राजधानी है, कम से कम इसके अंदर तो स्वच्छ भारत अभियान कामयाब हो जाता! लेकिन विफल हो गया। दिल्ली सरकार का दिल बड़ा है और दिल्ली सरकार ने, जबकि नगर निगम की यह जिम्मेदारी है– कूड़ा हटाना, सफाई करना, सेनिटेशन, सफाई कर्मचारी इनके जिम्मे में आते हैं लेकिन हमने फिर भी कहा कि 'कूड़ा– फ्री' दिल्ली करेंगे, 'मलबा–फ्री' दिल्ली करेंगे और वेंकैया नायडू जी को यह विश्वास दिलाया कि दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका जो रवैया है, वो दुश्मनों वाला है। दिल्ली के अंदर सरकार है, विधायकों से कहा जाता है कूड़ा साफ नहीं हो रहा, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, बरसाती नालियाँ, मानसून आने वाला है, हो नहीं रही है, बरसाती नालियों को सीवर में डाल रखा है। सीवर ओवर फ्लो कर जाते हैं और कहते हैं कि सीवर ओवर फ्लो कर रहे हैं। ये हालात इन लोगों ने बना कर रखे हुए हैं। भ्रष्टाचार तो एम.सी.डी. में कितना बढ़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं। ये रिपोर्टें आई है कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, लेकिन दिल्ली पुलिस से भी सात गुना ज्यादा एम.सी.डी. भ्रष्ट है। बाकायदा पी.एच.डी. करने का विषय बन चुका है कि कोई भी डिपार्टमेंट इतना ज्यादा भ्रष्ट कैसे हो सकता है! यह सच्चाई है, महाकरप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एम.सी.डी. बन चुका है। मैंने कल भी कहा था। कल की जो घटना हुई, वो घटना इसलिए थी कि इनको एक टोपी वहां पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनको मालूम है कि आने वाले इलैक्शन में इनके

पार्षद आने वाले हैं, इनके मेयर बनने वाले हैं और एक छटपटाहट हो गई है इनके अंदर। इसको कैसा रोका जाये। ये हिंसक तौर पर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज यह कहता हूँ, एक विधायक के तौर पर भी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने, इसी सदन ने यह मेरा हक है कि मैं यह जानूँ कि जो पैसा इनको दिया गया था नगर निगम को, अगर वो बजट इस सदन ने पास किया था तो एक सदस्य के तौर पर मेरा हक है, यह जानने का कि उस बजट का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ लगा? वो सही लगा कि नहीं लगा? उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ ? यह मुझे जानने का हक है। उसका ऑडिट होना चाहिए जो नगर निगम ने खर्चे किए हैं। जिस तरह से बजट का खर्चा कर रहे हैं। करते क्या है ? ये कह देते हैं कि उनकी सैलरी नहीं मिली, वो हड़ताल पर चले गये। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो सैलरी है, वो प्लांड बजट से जाती है, वो योजनागत व्यय होता है, जब योजनागत व्यय में कोई कटौती ही नहीं हुई तो आप किसी का वेतन कैसे रोक सकते हैं ? नॉन प्लान बजट अलग होता है, तो सैलरी आपने कैसे रोक ली? तो इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एम.सी.डी. के अंदर जो भी इनके खाते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इन्होंने काम किये हैं, जो भी भ्रष्टाचार किया है, उसके सारे के सारे रिकार्ड्स जब्त कर लिये जाये। अगर ये नहीं करेंगे, ये जाते–जाते या तो रिकार्ड में कोई न कोई गड़बड़ी करेंगे या उसको आग लगा देंगे क्योंकि एम.सी.डी. से ज्यादा भ्रष्ट कोई भी संस्था इस समय देश के अंदर नहीं है। अभी विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं है लेकिन मैं एक बात बड़ी गम्भीरता से उठाना चाहता हूँ कि ये बार–बार कहते हैं कि चौथे वित्त आयोग को

लागू करो, नगर निगमों के साथ भेदभाव हो रहा है तो मैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर कोट करना चाहता हूँ। यह सिर्फ उसका एक पक्ष देखते हैं। मैं, इसमें पेज नंबर 197, इस फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को रखता हूँ, यह कहती है

"we have examined the existing municipal laws and are of the view that the provision of Section 113 of the Delhi Muncipal CorporationAct,1957And Section 60 of the new Delhi Municipal CouncilAct, not more than mere enumeration of certain states or… revenues in list-2"

मतलब जो दिल्ली की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, जो उसके लिस्ट 2 में, 7 शेड्यूल में जो उसका हक बनता है, उस हक को मारने के लिए यह म्यूनिसिपल लॉज बनाये गये हैं। यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ। इसी 198 पेज पर, कहती है कि नगर निगम करों की उगाही नहीं कर पा रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार है, नगर निगम जब करों की उगाही नहीं कर पाता और वो करों की उगाही दिल्ली सरकार को करनी चाहिए, अगर दिल्ली सरकार वो करों की उगाही करेगी तो ज्यादा करों की उगाही होगी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ज्यादा पैसा दे पायेगी। एक बड़ी ही गम्भीर बात जो इसमें लिखी है, अध्यक्ष महोदय, आप जरूर सुनियेगाः

"we also notice that the Union Territories of National Capital, Delhi and the Puducherry are being punished by the Central Government."

यह फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को, जो पूर्ण राज्य नहीं है और पुदुचेरी को पनिश किया जा रहा है, सज़ा दी जा रही है केन्द्र सरकार की तरफ से

"and the Puducherry are being punished by the Central Government by withholding release of their respective share in the Union revenue just because these Union Territories have an elected legislature and Government."

क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, उनको पनिश किया जा रहा है, जो उनका हक बनता है सेंट्रल टैक्सेज में, वो नहीं दिया जा रहा है। 325 करोड़ रुपये देकर समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सवा लाख करोड़ रुपये दिल्ली से जो टैक्स होता है, वो उसको नहीं दिया जा रहा है। यह फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। ये लेकर आ जाते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो म्युनिसिपल कारपोरेशन को देना है, वो तो लेकर आ जाते हैं लेकिन जो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को छूट देनी है, उसके बारे में बोलने को राजी नहीं है। यह वही फोर्थ फाइनेंस कमीशन कह रहा है:

"The Central Government should withdraw its control over matters relalting to legislation of laws"

वो इसलिए कह रहे हैं कि नगर निगम को यह हक नहीं है कि वो लॉ पास कर सके। जब एक राज्य में सरकार है तो उससे संबंधित लॉज को पास करेगी तो दिल्ली की सरकार करेगी यह एडहॉकिज्म चल रहा है

और यह फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, यह फोर्थ फाइनेंस कमीशन कहता है

> "we feel that the Central Government which has the primary responsibility of funding the Union Territories and it is, in fact, meeting the financial requirments of Union Territories without legislature in full, cannot deprive the Union Territory of NCT of Delhi of its share in the revenue collected by MCD of Delhi in regard to matters included in the Union List because it has its own legislature."

सर, इसलिए कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, तो आप उसके हक को, उसके टैक्सेस के आप उससे उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। स्टॉम्प ड्यूटी के ऊपर, दिल्ली सरकार को स्टॉम्प ड्यूटी लगाने का हक मिलना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि आपको परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जो हक मिलने चाहिए, वो दिल्ली सरकार यानी दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़े, यह फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कह रही है और तो और मैं लास्ट में यह बताना चाहता हूँ जो पुलिस गड़बड़ कर रही है, उसके बारे में कहा है:

> "The Government of the National Capital Territory must take up the matter relating to statutory conflict ofAuthoritiesAppointed under the municipal law and the Delhi PoliceAct,1978 particularly because a regulation making powers of the Commissioner of Police exceed the statutory limits of municipal laws encacted by Parliament."

वो कहते हैं कि इसको यह हक कैसे मिले हुए हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ? ये कहते हैः "The Government must stop the Commissioner of Police page no.202, Fourth Finance Commission, the Government must stop the Commissioner of Police and the establishment from overtaking the public policy."

वो ओवर टेक कर रहे हैं, पुलिस वाले। पुलिस कमिश्नर ओवर टेक कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी को, यह हक है दिल्ली विधान सभा का

"on regard in haltingAnd parking of vehicles. Continued conflict has arisk of the motor vehicles tax being declared ultra vires of the Constitution. तो संविधान की अवहेलना हो रही है। जब भी आते हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, पहले कह रहे थे कि इस विधान सभा में आप पेश नहीं कर रहे हैं, ये पेश भी हो गई और हम इसको लागू करने के लिए भी तैयार है लेकिन टोटेलिटी में आप दिल्ली को उसका हक दे दो। आप दिल्ली को उसका हक नहीं दे रहे हो। 325 करोड़ रुपया आपने रोक कर रखा हुआ है। आप इसको टोटेलिटी के अंदर लागू करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री जरनैल सिंह (आर.जी.) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं बस ज्यादा नहीं, आखिर में यह कहूँगा, अपनी लोकल विधान सभा की भी बात कर दूँ। हमने अपने यहाँ सीवर का काम करना शुरू किया। पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क थी, हमने बनवा ली। लेकिन जो एम.सी.डी. की सड़क है सीवर जो वहां पर

डाल दिया, लेकिन आज तक नहीं बनी। वहाँ पर एक यू.जी.आर. है, पानी की दिक्कत हो रही है, पिछले जो हमारे विधायक थे, उन्होंने वो यू.जी.आर. बनवाना शुरू किया। जगह एम.सी.डी. की, जब पूरा होने का वक्त आया, जब मैंने अपना फंड दिया तो उन्होंने ही एन.ओ.सी. देने से इंकार कर दिया। खुद काम शुरू करवाया, लेकिन अब जब मैं काम करवाना शुरू करता हूँ तो एन.ओ.सी. नहीं देंगे। हमारे एन.ए. ब्लॉक में आठ महीने हो गये, सीवर का काम हो गया, लेकिन आज तक उसकी सड़क नहीं बन सकी। आठ महीने हो गये, चैक दिया हुआ हैकृ 80 लाख रुपये, एक और आर.आर. कट दिये हुए हैं, लेकिन हमें काम नहीं करने दे रहे। चांद नगर में, आज सुबह जब मैं था, वहाँ पर एक दिक्कत हो रखी है– कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, लोग कह रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा है, सीवर का पानी कहीं मिक्स हो रहा है, उन्होंने चैक करना है, सड़क तोड़नी है, जे.ई. आ गया, एफ. आई.आर. कर दी। उन्होंने जलबोर्ड को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे तौर पर हो रहा है, पार्किंग का मसला राजौरी गार्डन के अंदर वो आज तक पार्किंग नहीं बन सकी। तो ये एम.सी.डी. एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। फोर्थ फाईनेन्स कमीशन कहता है कि दिल्ली सरकार को हक दिया जाए जिससे ये रेवेन्यू ज्यादा उगाह सकें। अगर ये आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर केन्द्र की सरकार जानबूझकर दिल्ली सरकार को तंग कह रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मुझे इतना बोलने का वक्त दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी, थोड़ा हम सभी संक्षेप में रखेंगे लगभग 15–16 विधायकों ने बोलना है मैं चाहता हूं समय से पूरा हो।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और इस पूरे सदन का ध्यान तीनों निगमों में जो कि भा.ज.पा. शासित निगम हैं, उनमें चल रहे भ्रष्टाचार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली नगर निगम जिसको विशेष रूप से दिल्ली में साफ–सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर कोई विदेश से मेहमान भारत में आये और दिल्ली की इस दुर्दशा को देखे तो उससे हमारे देश की छवि एकदम धूमिल हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में कहीं भी चले जाएं, किसी भी ग्रामीण बस्ती में चले जाएं, रिसेटेलमेंट कालोनी में चले जाएं, झुग्गी बस्ती में चले जाएं, जहां भी जाएं, वहां कूड़े का अंबार नजर आता है। जितने भी ढ़लावघर हैं, उसकी स्थिति को देखें तो कूड़ा ढ़लावघर के अंदर नहीं बल्कि आगे रोड तक कवर किया हुआ मिलेगा। मैं लगातार अपने क्षेत्र में विजिट करता हूं और जहां भी जाता हूं, आम जनता रोज केवल अगर कंप्लेंट करती है तो गंदगी को लेकर कंप्लेंट करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूंगा अभी पिछले दिनों नार्थ दिल्ली एम.सी.डी. के अंदर एक प्रस्ताव वहां के उस वक्त सदन के जो नेता थे, योगेन्द्र चंदोलिया जी और जो स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन थे, भारद्वाज जी उन लोगों ने मिलकर एक दबाव बनाया कि ये जो प्रति मिट्रिक टन कूड़ा उठता है, उसका ठेका जिन चार कंपनियों को देने के लिए दबाव बनाया कि 1300 रूपये प्रति मिट्रिक टन के हिसाब से उनको दे दिया जाए और जब ये बात उस वक्त के महापौर ने, रविन्द्र गुप्ता जी ने उससे इंकार किया तो लिटरली आपस में उनमें लड़ाई हो गई और लड़ाई इस कदर बढ़ी कि

रविन्द्र गुप्ता जी ने अपने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतीष उपाध्याय जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने यह आरोप लगाया कि चंदोलिया जी और भारद्वाज जी दोनों ने कहा है कि ये आदेश ऊपर से आया है यानि सतीश उपाध्याय जी की तरफ से आया है। जो काम 475 रूपये प्रति मिट्रिक टन जो डायरेक्ट खुद नार्थ एम.सी. डी. अपना काम करवा रही थी, कूड़ा उठाने का ई.डी.एम.सी. 470 रूपये में जिस कूड़े को उठवाने का काम करवा रही थी, ऐसी कौन सी मजबूरी, लाचारी थी कि उसी काम को उठाने के लिए एम.सी.डी. ने 475 की बजाय 1300 रूपये में उसका ठेका दे दिया। ये निहायत शर्म की बात है! ये सीधा–साधा करप्शन का मामला सबके सामने आता है। एक तरफ दिल्ली की जनता परेशान है तो दूसरी तरफ एम.सी.डी. के कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर परेशान हैं लेकिन वहीं दिल्ली के एम.सी.डी. के नेता किस तरीके से बंदरबांट में लगे हैं... 475 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से जो कूड़ा उठना चाहिए, उसको 1300 करोड़ में उठाने का ठेका दे देते हैं। अभी दो दिन पहले की बात है, परसों जो नये मेयर चुनकर आये और नये स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरमैन चुनकर आये उन लोगों ने परसों फिर से सितम्बर तक के लिए 6 महीने के लिए 1300 करोड़ के मिट्रिक टन के हिसाब से उन्होंने उसे ठेके पर दे दिया जो निहायत ही शर्म की बात है और इस तरह का भ्रष्टाचार एम.सी.डी. करके अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखती कि किस तरह जनता की मेहनत की कमाई को एम.सी.डी. में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता लुटाने में लगे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1178 रूपये प्रति मिट्रिक टन से लेकर 1305 रूपये प्रति मिट्रिक टन के हिसाब से इन्होंने ठेका दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी पीछे हम देख रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली की सरकार जो फ्लाई ओवर्स बना रही है, समय से पहले उन फ्लाई ओवर्स के निर्माण को पूरा कर रही है। तीन फ्लाई ओवर्स में लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रूपया हमारी सरकार ने बचाया लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित निगम की सरकार है। दिल्ली में दो फ्लाई ओवर्स – एक बिजवासन के अंदर और दूसरा फ्लाई ओवर रानी झांसी रोड पर जो सेंट स्टीफन हास्पिटल से फिल्मिस्तान तक जाता है, उसका निर्माण पिछले लगभग आठ सालों से लगातार चल रहा है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक वो निर्माण केवल साठ प्रतिशत पूरा हो पाया है और जिसको बनाने में 177 करोड़ रूपया तय किया गया था, उसमें केवल साठ प्रतिशत काम जिसको करने में लगभग आठ साल लगा दिये। उसमें 200 करोड़ से ज्यादा पैसा अब तक उसके निर्माण में व उसमें जो लैण्ड एक्वायर होती है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उस पर अब तक खर्च किया जा चुका है। यानि कि 177 करोड़ वाला खर्च भी लगता है कि 300 करोड़ में जाकर पूरा होगा और दूसरी तरफ जो बिजवासन वाला फ्लाई ओवर है, जिसको बनाने के लिए लगभग 44 करोड़ रूपया तय किया गया था, उस पर 58 करोड़ से ज्यादा वो अब तक खर्च कर चुके हैं जबकि केवल साठ प्रतिशत काम हुआ है। लगता है उस पर भी दुगने से भी ज्यादा पैसा ये लोग खर्च करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ आपका ध्यान एक और घोटाले की तरफ ले जाना चाहता हूं। अभी एम.सी.डी. के अंदर ई.डी.एम.सी. के अंदर

उन्होंने मच्छरदानियां खरीदी और मच्छरदानी खरीदने की कभी जनता ने मांग नहीं की थी। आखिर ये मच्छरदानियां किसलिए खरीदी हैं ? करोड़ों रूपये किसलिए खर्च किया गया है? ताकि ये डेंगू से रोकथाम कर सकें लेकिन सभी को पता है कि डेंगू के मच्छर रात में नहीं, दिन में काटते हैं। फिर आखिर ये मच्छरदानियां एम.सी.डी. के द्वारा क्यों खरीदी गई ? इनकी जरूरत क्या थी ? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है जो 'मच्छरदानी घोटाले' के नाम से भविष्य में जाना जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बस एक मिनट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लगातार नोटिस कर रहा हूं, बल्कि मेरे साथ–साथ बाकी सम्मानित साथी भी नोटिस कर रहे होंगे कि जहां भी कहीं किसी गरीब का मकान पुराना हो जाता है, जो टूटने की दशा में आ जाता है, वो उसको दोबारा से तोड़कर या उसकी मरम्मत करते हैं तो वहीं पर एम.सी.डी. के इंजीनियर्स पहुंच जाते हैं। उनको डी.एम.सी. एक्ट की धारा 445 के अंदर, धारा 439 के अंदर उनको नोटिस दिया जाता है, उनको भयभीत किया जाता है ताकि वो लोग जाकर इंजीनियर्स से मिलें, उसके बाद सेटिंग कर ली जाती है और जब वो लोग उनको पैसा दे देते हैं तो जिस निर्माण को अवैध बताया जा रहा होता है, वही निर्माण पैसे मिलने के बाद वैध घोषित हो जाता है। यह अपने आप में बेहद शर्म का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी शासित निगम लगातार दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। साफ–सफाई के साथ तो धोखा है ही, ये 'स्वच्छता अभियान' ये लगता है एक जुमला साबित हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो दिल्ली सरकार इनको पैसा देती है निगम को, उस निगम को पैसे देते समय एक शर्त लगा दी जाए कि नॉन–प्लान का पैसा जो सेलरी के लिए दिया जाता है, वो सेलरी से अलग किसी और मद में खर्च न किया जाए बल्कि सेलरी में दिया जाए और साथ ही साथ इनके खर्चों की, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए इनका आडिट होना चाहिए, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं कल से इंतजार कर रही थी। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि लगभग दस साल भा.ज.पा. दिल्ली नगर निगम में अपने पूरे करने जा रही है अगले साल और दस सालों के इनके भ्रष्टाचार को दस मिनट में समेटना मेरे लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं अपनी अगर एक विधान सभा में 70 विधान सभा पूरी दिल्ली में भा.ज.पा. के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगी, सिर्फ अपनी ही चांदनी चौक विधानसभा से मैं अगर शुरूआत करूं तो ये जो नारा है मोदी जी का कि देश आगे बढ़ रहा है, मैं ये कहूंगी कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, भा.ज.पा. वाले और उनके परिवार जरूर आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं पूछना चाहूंगी संजय गौतम, जिसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें नगर निगम में लोगों ने दी हुई है, ये संजय गौतम आखिर है कौन ? विजेन्द्र गुप्ता जी बैठे होते तो जरूर बताते

कि संजय गौतम से विजेन्द्र गुप्ता जी का रिश्ता क्या है। अब वो बताने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं; इसलिए मैं बताती हूं कि संजय गौतम जी जो हैं, वो उनकी धर्मपत्नी जो हैं, शोभा गुप्ता जी, उनके सगे भाई हैं और विजेन्द्र गुप्ता जी के साले हैं। अब आगे बढ़ती हूं। तो आप सोचेंगे कि मैं उनका जिक्र यहां कर क्यों रही हूं ? नगर निगम में सबसे पहली बात पार्किंग का जो ठेका है, वो एक–दो नहीं; अभी नगर निगम में चालीस पार्किंगों के ठेके का प्रस्ताव निकाला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चालीस... ये मेरे हाथ में हैं; चालीस पार्किंग के ठेकों का जब टेण्डर निकला, उसमें एक ईदगाह पार्किंग भी है जिसका जिक्र तब इसमें नहीं है, उसको जब टेण्डर किया गया तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि वो पार्किंग पूरी तरह से जो विजेन्द्र गुप्ता जी के साले हैं, वो चला रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात, इसके जो तीन साल पुराने रेट हैं, उस पर ये चलाई जा रही हैं जो कि आज के रेट के हिसाब से जो पैसा नगर निगम को एक ठेकेदार को देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो विजेन्द्र गुप्ता जी के साले संजय गौतम है इनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि एक अनिल शर्मा हैं, वो कौन हैं? वो बी.जे.पी. के चांदनी चौक जिला के कोषाध्यक्ष हैं जिनके पास, पूरी उगाही करके जो इनके भा.ज.पा. के कार्यालय के खर्चे हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी के, वो भरने की जिम्मेदारी रहती है। अब वो उगाही कहां से करते हैं ? वो संजय गौतम जी के साथ मिलकर चांदनी चौक विधान सभा में ही अध्यक्ष जी, सात जून को.... मेरा दफ्तर है– कश्मीरी गेट उर्दू एवं सिंधी अकेडमी के अंदर और लगातार मैं

रोज देख रही हूं कश्मीरी गेट में अवैध रूप से पार्किंग पूरे रोड पर होती है। सात तारीख को जब मुझे लगा कि लगातार शिकायतों के बाद कुछ नहीं हो रहा, मैंने 100 नंबर पर फोन किया। पुलिस आई। मैंने डी.सी., सिविल जोन को फोन किया, उनकी टीम वहां पहुंची। मैंने डी.एम. को फोन किया और डी.एम. की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर जो पार्किंग माफिया हैं, उनके हाथों से बहुत सी ढ़ेरों चाबियां गाड़ी की जब्त की गई और गिनती की गई। उस समय मेरे सामने जो गिनती हुई थी, 378 गाड़ियां खड़ी थी उस समय और सबकी चाबियां जो ठेकेदार खड़े थे, उनसे ली गई और उनसे जब पूछा गया कि पर्ची दीजिये, एक पर्ची नहीं थी उनके पास दिखाने के लिए, देने के लिए और ये उगाही का धंधा कोई और नहीं पूरे सबूत हैं आज विजेन्द्र गुप्ता जी होते तो बताते कि इनके साले को किस तरीके से ये पार्किंगें मिल रही हैं। किस तरीके से अनिल शर्मा जो चांदनी चौक से जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं उनके साथ चल रहा है, मैं यहां ही नहीं रूकूंगी, अध्यक्ष जी, ये अखबार की कटिंग है। ये 130 साल पुरानी हरदयाल लाईब्रेरी है, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अंदर चलती है। ये 2002 की प्रेस कटिंग है जिसमें बी.जे.पी. के जब हमारे पार्षद थे विजेन्द्र गुप्ता जी, उन्होंने प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया, आरोप क्या था? उस समय की जो कांग्रेस की मेयर थी और उन पर आरोप था कि ये जो लाईब्रेरी की सेक्रेटरी बिना चुनाव किये किसी को नियुक्त किया गया है और यहां पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। आप जानेंगे कि जब गुप्ता जी को मौका मिला, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। इन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन इन्हें भी मौका मिल जाएगा। जो कांग्रेस से सीख ली, इन्होंने भी किया। इन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें इन्होंने

अपनी धर्मपत्नी शोभा गुप्ता जी, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं जिसमें लिखा है कि इन्होंने बिना चुनाव किये किस तरीके से मेयर के साथ मिलकर उस समय के जो मेयर, चेयरमैन ऑफ द कमेटी, आजाद सिंह जी थे, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को हरदयाल लाईब्रेरी का सेक्रेटरी नियुक्त करवा लिया, बिना चुनाव के। उसके बाद वहां की जो भी हेराफेरियां थी, वो वहां की इन्क्वायरी कमेटी में पहुंची और इन्क्वायरी कमेटी ने इनके चुनाव को रद्द कर दिया। उनको हटा दिया लेकिन फिर किसी तरह भी वो आज की तारीख में उन्हें चुनकर वापस ले आये और वो आज भी हरदयाल लाईब्रेरी की सचिव हैं। इतना ही नहीं, वो एल.जी. के दफ्तर में जाती हैं और एल.जी. से पैसे की मांग करती हैं और एल.जी. के पास दिल्ली सरकार के लिए पैसा नहीं है, पर शोभा गुप्ता जी जब जाती हैं, विजेन्द्र गुप्ता जी के साथ, तो तीन करोड़ रूपया एल.जी. एक सेकेण्ड नहीं लगाते हैं उन्हें हरदयाल लाईब्रेरी के लिए दे दिये जाते हैं और हरदयाल लाईब्रेरी के लिए जब पैसे दिये गये अध्यक्ष जी, उसमें से आज तक एक भी किताब खरीदी नहीं गई है लेकिन ये सुनने में आया है कि शोभा गुप्ता जी और एल.जी. के दफ्तर से एक और शख्स हैं और एक हरदयाल लाईब्रेरी की जो हैड हैं, ये चारों लोग इसी महीने एक–दो दिन के अंदर लंदन दौरे पर जा रहे हैं। वहां सीखने–देखने जा रहे हैं सरकार खर्चे पर। लाईब्रेरी के लिए जो तीन करोड़ मिला है, उस खर्चे पर देखने जा रहे हैं कि हरदयाल लाईब्रेरी को कैसे ठीक किया जाए लेकिन किताब एक भी नहीं खरीदी जाती। ये हरदयाल लाईब्रेरी जिसकी दिल्ली भर में ब्रांचें हैं, खासतौर से मैं नार्थ एम.सी.डी. की बात करती हूं– जो भर्तियां की गई हैं, आप देखिये कौन लोग हैं?

आधे से ज्यादा आप पाएंगे इनके दूर के, नजदीक के रिश्तेदार हैं और जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सातवीं पास, नवीं पास, बारहवीं फेल... ये मैं आपको सारे तथ्य दे दूंगी। इन लोगों की नियुक्तियां, ये विजेन्द्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी शोभा गुप्ता जी जब से हरदयाल लाईब्रेरी में आई हैं, ये तब से हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं परिवार की बात पर यहीं नहीं रूकूंगी। मैं आपको एक और लेटर दिखाती हूं – निगमबोध घाट, सब लोग जानते हैं निगमबोध घाट... और सुमन गुप्ता जी कौन हैं? सुमन गुप्ता जी आज चांदनी चौक से भा.ज.पा. के जिलाध्यक्ष हैं, सुमन गुप्ता जी भी नगर निगम पार्षद रहे हैं और जब सुमन गुप्ता जी चेयरमैन थे , उन्होंने निगमबोध घाट, सर जो दिल्ली नगर निगम के अधीन श्मशान घाट जो आते हैं, उसे एक समाज को दे दिया गया कि इसकी देख–रेख, रख–रखाव ये समाज करेगा और जब उस समाज को वो सौंप दिया गया, उसके बाद चेयरमैन का अपना टेन्योर सुमन कुमार गुप्ता जी पूरा करने के तुरंत बाद उस समाज के अध्यक्ष के पद पर आ जाते हैं और उनके आ जाने के बाद सुमन कुमार गुप्ता जी यहीं नहीं रूकते, अध्यक्ष बन गये अब करोड़ों रूपये का वहां पर दान आ रहा है जिसका कोई ऑडिट नहीं है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है? और ये मांग किसी और ने नहीं, सबसे बड़ी इंट्रेस्टिंग बात देखिये, इन्हीं की जो नगर निगम पार्षद हैं चांदनी चौक से, उन्होंने सुमन गुप्ता जी के खिलाफ, क्योंकि उनकी कोई पालीटिकल या अपनी कोई लड़ाई होगी लेकिन उन्होंने नगर निगम में पूछा कि मैं चांदनी चौक विधानसभा की पार्षद हूं और सुमन कुमार गुप्ता जी करोड़ों रूपये का वहां पर घोटाला कर रहे हैं और वहां पर सबसे बड़ी बात क्रिमिनेशन इलेक्ट्रिकल और सी.एन.जी. से भी होता है लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो बंद रखा

हुआ है। क्यो? क्योंकि ये भी सुनने में आया है... मैं नहीं कह रही हूं – यहां पर जो इनकी सुरेखा गुप्ता जीं निगम पार्षद हैं, उन्होंने अपने मिनट्स में पूछा है कि वहां जो लकड़ी बिक रही है, जो सामग्री बिक रही है वो भी सुमन कुमार गुप्ता जी के रिश्तेदार हैं तो अगर क्रिमिनेशन इलैक्ट्रिकल से होने लग जाएगा तो लकड़ियों की बिक्री खत्म हो जाएगी और वहां पर इस तरह का काम सुमन कुमार गुप्ता जी कर रहे हैं। ये सुरेखा गुप्ता जी के एक–एक .में है और बिल्कुल निगम से पूछा कि आप इसका आडिट कर रहे हैं और इन्हें सात नंबर पर जो प्रश्न है, उसका जवाब नगर निगम ही दे रहा है कि इसका कभी भी आडिट नहीं हुआ और इसका जो पैसा आ रहा है, वो भी कहां से आ रहा है? उसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि नगर निगम के क्रिमिनेशन ग्राउंड और एक बेला रोड पर भी क्रिमिनेशन ग्राउंड है, अध्यक्ष जी, करोड़ों रूपया उस क्रिमिनेशन ग्राउंड पर इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन के लिए खर्च कर दिया गया लेकिन आज तक वो खुला नहीं है। पूछा जाए कि कौन जिम्मेदार था? किसने करोड़ों रूपया लगाया और आज करोड़ों रूपया लगाने के बाद भी बेला रोड जो मेरे चांदनी चौक विधानसभा के अंदर क्रिमिनेशन ग्राउंड आता है, वो बंद कैसे है? अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं इस कमेटी के अंदर जो निगम बोध घाट की कमेटी के जो सदस्य हैं, वो भी बड़े इंट्रेस्टिंग हैं। सुमन कुमार गुप्ता जी उसके अध्यक्ष हैं लेकिन उनके दामाद, उनके समधी, उनके बेटे, उनके भाई का बेटा आप अगर लिस्ट चेक करेंगे, वो भी मैं अभी आपको सौप देती हूं। वो सब उनके रिश्तेदार हैं जिनकी वहां पर किसी को लकड़ी बेचने का किसी को... माफी चाहूंगी कफन बेचने को धंधे के रूप में निगम बोध घाट... क्योंकि बहुत वीवी.

आई.पी. आते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कमाई हो रही है लेकिन दुख की बात यह है कि नगर निगम का वो क्रिमिनेशन ग्राउंड है जिसकी कतई भी आडिट आज तक नहीं हुई है। तो मेरा यह कहना है और सबसे बड़ी बात एक और चीज जब मैंने सात जून को मेरे आफिस के बाहर जो कश्मीरी गेट उर्दू, सिंधी अकादमी के अंदर है, मैंने इसका विरोध किया जैसे मैंने बताया नगर निगम की पार्किंग खुद विजेन्द्र गुप्ता जी के साले चला रहे हैं। डी.सी., डी.एम., तहसीलदार, पुलिस वहां पहुंची तुरंत, वहां पर जो लोग अवैध उगाही कर रहे थे, जिनके पास पर्ची नहीं थी, उन्हें पकड़ा गया और अगले दिन आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचती हूं तो मुझे कहा जाता है आपके दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है, कारण बताओ कि क्यों मेरे दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है? कह रहे हैं कि यहां विधायक का दफ्तर हो ही नहीं सकता। आप सोचिये! सात तारीख को मैं विराध करती हूं डी.एम., पुलिस के सामने इन सभी माफियाओं को पकड़वाती हूं और इसकी अब जांच भी आज भी मैंने डी.सी. और डी.एम. को लिखा है कि उस दिन जो छापेमारी हुई, जो लोग पकड़े गये, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई का यही नोटिस आया कि मुझे जो भी दफ्तर सरकार ने दिया, वो गलत तरीके से दिया। वहां तो हो ही नहीं सकता, इस तरह आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर जो ये है, ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, वो हम लोग लड़ रहे हैं! ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।

एक लास्ट उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगी क्योंकि वो ही मैने कहा अगर मैं भाजपा का भ्रष्टाचार बताने लग जाऊं तो दस मिनट कम

हैं। चांदनी चौक टाउन हाल ऐतिहासिक जगह है, सब जानते हैं पुराना नगर निगम वहीं चला करता था। वहां पर एक स्विमिंग पुल बनाया गया। दोबारा करोड़ों रूपये उस स्विमिंग पुल पर खर्च किये गये। लोग लगातार मांग करते रहे कि करोड़ों रूपये खर्च करके लोगों की मांग पर ये स्विमिंग पुल बना है तो इसे क्यों नहीं लोगों के लिए, बच्चों के लिए खोला जा रहा ?

अध्यक्ष जी, एक और बड़ी बात, जिन अनिल शर्मा की मैं बात कर रही हूं जो चांदनी चौक के कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हीं के सगे भाई मनोज शर्मा को वो स्विमिंग पुल दे दिया गया है और अध्यक्ष जी, वहां के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये नगर निगम का था, ये हमारे आम आदमी, गरीब परिवार के बच्चों के लिए जो वहां रहता है, मध्यमवर्गीय परिवारों, उनके बच्चों के लिए था और कहा ये गया था कि महीना पांच सौ रूपया फीस होगी और हकीकत ये है कि उनके सगे भाई को इसका ठेका दे दिया जाता है और वो स्विमिंग पुल के महीना चार और पांच हजार रूपये में जो है, वो एक बच्चे से फीस ली जा रही है तो मैं ये कहूंगी कि इस तरीके से जो देश नहीं बढ़ रहा बी.जे.पी. और उनके परिवार बढ़ रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इस स्विमिंग पुल को तुरंत लोगों से जो फीस का वायदा था कि पांच सौ रूपया प्रति बच्चा हर महीना स्विमिंग के लिए लिया जाएगा, आज अनिल शर्मा जो सगे भाई हैं मनोज शर्मा और गौतम जिनकी मैं बात कर रही हूं ,उनके साले हैं, उनके साथ मिलकर वो आज चला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन सबकी जांच आप कराएं और लास्ट कस्तूरबा गांधी हस्पताल की ...क्योंकि मैं जो भी बात कर रही

हूं वो सात, आठ, नौ तारीख को कल तक वहां पर होकर आयी हूं। कस्तूरबा गांधी अस्पताल, मैं फिर कहूंगी जामा मस्जिद इलाके में आती है, दिल्ली नगर निगम का अस्पताल है। मैं खुद उस अस्पताल में गयी। अध्यक्ष जी, उस अस्पताल में जो गरीब को पर्ची है, पांच रुपये की बनती है। पर मेरे पास ऑन वीडियो रिकार्डिंग्स हैं। वहां के लोगों ने बताया कि पर्ची बनाने के लिए पांच रुपये नहीं पचास और सौ रुपये उन्हें देना पड़ रहा है। इन लोगों ने यह तथ्य वहां रखे, उसके बाद मैं एम.एस. के आफिस तक गयी तो एम.एस. को लोगों ने बाहर गए हुए बताया। तो अगर एम एस. से मिलना है तो उन्हें 500 रुपया देना पडता है। अगर आपको एम.एस. तक जाकर काम कराने हैं। वहां पर दवाईयां नहीं थी, वहां एक्सरे नहीं हो रहे लोगों के और लोगों से रिश्वत और मार–पिटाई भी की जाती है। अगर आप पैसा नहीं देंगे और आप जबर्दस्ती वहां पर अगर कुछ लोग अपनी बात उठाना चाह रहे हैं तो उनसे मार कुटाई तक हुई। यह कस्तूरबा गांधी, जामा मस्जिद नगर निगम के अस्पताल की हालत है और अच्छा हुआ मैं वहां तक पहुंच गयी, वरना यह कहा गया कि यह अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है, क्योंकि लोग अंजान है। लोगों को भी जानकारी हम दे रहें हैं। मैंने उनको कहा कि आप आइए अरूणा आसफ अली अस्पताल, दिल्ली सरकार के अधीन है। मैं चेयरमेन हूं। जो यहां पर दवाई नहीं मिल रही है। जो यहां इलाज नहीं हुआ, हम वहां पर करके दिखायेंगे। लेकिन यह गुमराह करना कि दिल्ली सरकार यहां पर दवाइयां नहीं दे रही है नगर निगम के अस्पतालों में, यह हमारे जो पार्किंग माफिया हैं, यह हमारे संरक्षण में चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगी सारे सबूत और तथ्य कागज मेरे पास हैं। मैं सदन के

सामने रखूंगी, आपको दूंगी और इसकी जांच हो, सिर्फ एक चर्चा बन कर न रहे मैं उम्मीद करती हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग।

श्री विजेन्द्र गर्ग : आदरणीय अध्यक्ष महोदय। दिल्ली की जनता को महसूस करते हुए एम.सी.डी. के काले कारनामों और भ्रष्टाचार पर आपने इस विशेष सत्र का आहवान किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय आज एम.सी.डी.ी की परिभाषा ही बदल गयी। कभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली होता था और यह मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली हो गया है। आज लोग म्यूनिसपल कारपोरेशन को 'कर परेशान' के नाम से जानने लगे हैं। आज हमारे कार्यालयों में जो जनता आती है, उस जनता की जो शिकायत होती है, उनमें 70 प्रतिशत शिकायतें दिल्ली नगर निगम से संबंधित होती है। 10 प्रतिशत शिकायतें दिल्ली पुलिस से संबंधित होती है। 10 परसेंट डी.डी.ए से और केवल 10 परसेंट शिकायतें दिल्ली सरकार के कार्यकलापों से होती है, जो रोजमर्रा की शिकायत होती है, छोटी–मोटी शिकायतें होती हैं, जिनको हम अपने लेबल पर करा लेतें हैं, लेकिन जो दिल्ली नगर निगम की शिकायतें हैं, उनके लिए अगर हम दिन–रात भी जूझतें रहें तो वह समस्याएं हल नहीं हो पाती। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को साफ–सुथरा रखना, दिल्ली को स्वस्च्छ रखना दिल्ली नगर निगम की जिम्मेवारी है। परन्तु, दिल्ली नगर निगम इस काम में तनिक भी उनको इस काम का कोई आभास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली को कूड़े के

ढ़ेर में तब्दील कर दिया है, जिसे देखकर प्रत्येक दिल्ली वासी का सिर शर्म से झुकता है। दिल्ली की सफाई को बदहाल देखकर माननीय उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि दिल्ली कूड़े का ढ़ेर बन कर रह गयी है। इन वाक्यों में भी माननीय उच्च न्यायालय का दर्द झलकता है। जगह–जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, नालियां, गलियां सड़के महीनो–महीनों सफाई नहीं होती उनकी, जिसके कारण मच्छर पनपते हैं। पिछले कुछ वर्षों से डेंगू, मलेरिया मच्छर जनित बीमारियों ने महामारी का रूप धारण किया हुआ है, जिससे प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में दिल्ली वासी मौत का ग्रास बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन मच्छरों के लिए जो दवाई एवं फोगिंन मशीन यह एम.सी.डी. खरीदता है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया जाता है और यह भा.ज.पा. के नेता फोगिंन मशीन के साथ केवल अपने चित्र खिंचवाते हैं और उनके बड़े–बड़े पोस्टर छाप देते हैं और यह डेंगू और मलेरिया के मच्छर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय 'घोस्ट एमप्लाईज' एम.सी.डी. के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण हैं। इनकी तनख्वाह का पैसा अधिकारी और पार्षद मिलकर डकार जाते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि ''पार्षद है मस्त जनता है पस्त''। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन स्वस्च्छ भारत की बी. जे.पी. पार्षदों ने सरेआम धज्जियां उड़ा रखी है।

पेंशन घोटाले की बात करें तो पिछले लगभग ढाई वर्षों से एम.सी.डी. के अंतर्गत आने वाली पेंशन जरूरतमंद लोगों को नहीं दी जा रही है। जब भी कोई लाचार विधवा, विकलांग एवं वृद्ध महिला पुरूष पार्षद के कार्यालय में जानकारी लेना चाहता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसको धक्के मार करके पार्षद के कार्यालय से बाहर निकाला जाता है। पेंशन देना

तो दूर, पार्षद इन बेसहारा लोगों को प्रताड़ित करता है। निगम की पेशन में पार्षदों द्वारा बड़े पैमाने पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। रोहिणी क्षेत्र की भी पार्षद श्रीमती शोभा विजेन्द्र गुप्ता, जिनका कि बार–बार जिक्र इस हाउस में हो रहा है, उनकी वार्ड में एक बड़ा पेंशन घोटाला उजागर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सभी वार्ड में पेंशन की जांच कराई जाये तो अधिकांश वार्डों में इसी प्रकार के पेंशन घोटाले उजागर होंगे। लाचार, बेसहारा, गरीब एवं जरूरतमंद के हक का पैसा जो पेंशन के जरिये उन्हें मिलना था, वो पैसा पार्षद डकार गये, ये कहां का न्याय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र राजेन्द्र नगर में जब कोई भी नागरिक पार्षद के कार्यालय में जाकर अपनी सड़क नाली गली आदि की मरम्मत के लिए फिर पार्कों के रख रखाव के लिए फिर एम.सी.डी. के अंतर्गत आने वाली लाईटों की मरम्मत के लिए कहता है तो पार्षद का टका सा जबाव होता है कि हमारे पास फण्ड नहीं है। अध्यक्ष जी, कितने आश्चर्य की बात है। 'एम.सी.डी. तो कंगाल है, पार्षद मालामाल है और जनता बेहाल है।' मेरे क्षेत्र में एम.सी.डी. के अंतर्गत आने वाली डिस्पेंसरी एवं निगम के स्कूलों का बुरा हाल है। निगम के स्कूल कई एकड़ भूमि पर बने हुए है। परन्तु वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए मूलभुत सुविधाएं नहीं हैं और न ही उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। यह सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. के संरक्षण में बिल्डर माफिया फल–फूल रहा है, लेकिन कोई जरूरतमंद व्यक्ति अपना परिवार बढ़ जाने पर अपने घर की छत पर एक छोटा सा कमरा भी बनाना चाहता है, तो एम.सी.डी. का बिल्डिंग विभाग उस व्यक्ति से उस कमरे की एवज में पचास हजार से एक लाख रू0 तक रिश्वत लेता है और यदि वो आदमी देने में असमर्थ

है तो उसकी उस कमरे को भी तोड़ दिया जाता है। यह सरासर अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. के अंतर्गत चलने वाली पार्किंग और कमर्शियल एडवरटाईजमेंट साइट्स में करोड़ों रूपयों का घोटाला प्रति वर्ष हो जाता है। पार्किंग और एडवरटाइजमेंट की साइट्स से राजस्व की जो वसूली होनी चाहिए वो एम.सी.डी. के पार्षदों एवं अधिकारियों की तिजौरी में चला जाता है। इस प्रकार से दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को भ्रष्ट एम.सी.डी. लूट रही है।

अध्यक्ष महोदय, सफाई में घोटाला, कर्मचारियों की सैलरी में घोटाला, संपत्ति कर में घोटाला, पार्किंग में एडवरटाइजिंग में घोटाला, इतने सारे घोटालों के बाद विकास एवं कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए फण्ड बचेगा कैसे अध्यक्ष जी ? दिल्ली की जनता ने बड़े अरमानों और उम्मीदों से दो बार दिल्ली नगर निगम की सरकार बी.जे.पी. को सौंपी थी। आज वही जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली में तीनों निगमों को तुरंत प्रभाव से भंग करें, चुनाव करायें जायें ताकि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार में डूबे इन तीनों निगमों से निजात मिल सके। जय हिन्द, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : साढ़े बजे हम पुनः मिलेंगे। आधा घंटे के लिए टी ब्रेक।

सदन अपराह्न 4:30 पर पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया और यह बड़ा गंभीर विषय है, जिस पर आज चर्चा हो रही है। एम.सी.डी. के बहुत सारे कारनामें मेरे दोस्तों ने गिनवा दिये हैं। मैं कुछ करेंट की सिनेरियों जो तीन चार दिन या पिछले दस दिन में जो घटनाएं घटी, उसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस दिन हमारे यहां पर यह सेशन हमने शुरू करना था, हमारे जो तीन महापौर हैं, उन्होंने आ के सबसे पहले विरोध जताया कि सेशन के ऊपर हमें विरोध है। अगर विधान सभा में किसी भी चीज पर चर्चा हो रही है तो उनको विरोध क्यों हो रहा है। कहीं न कहीं उनको पता चल रहा है कि उनकी जो दाल में काला है, उसका खोखलापन यह जो भ्रष्ट कार्यक्रम चल रहा है, उसका खुलासा हो रहा है। साथ में इन तीनों मेयर ने खुलकर यह कहा कि हमारी नालियां तो साफ है और पी.डब्लू.डी. की नालियां बिल्कुल साफ नहीं हुई हैं तो उसमें मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि पांच मई को साउथ एम.सी.डी. के कमिश्नर से मिटिंग होती है, जहां पर मिनट की यह कॉपी खुद उनके साइन किये हुए है। उसके ऊपर और वह लिख कर देते हैं कि हां, हमें मालूम है कि डिसिल्टिंग का कार्यक्रम हमारे यहां लेट चल रहा है, जिसको कि जून के तीसरे हफ्ते में कम्पलीट कर देंगे। ये आपके पास में अभी कॉपी भिजवा रहा हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है। तो वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने नालियां साफ नहीं की और यहां पर मेयर कह रहे हैं कि हमारी नालियां साफ हैं और कह रहे हैं कि पी.डब्लू.डी. की एक भी नाली साफ मिल जाये तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो परसों ही मैंने

पी.डब्लू.डी. के जितने चीफ इंजीनियर हैं उनको जितनी भी नालियां साफ हुई हैं, उनकी फोटोग्राफ्स उन्होंने सारा डाटा भेजा मेरे पास। तो पी.डब्लू. डी. की नालियां सारी साफ हैं तो आज इस सदन के माध्यम से मैं उन तीनों महापौर को बोलना चाहूंगा कि अब खुशी से इस्तीफा दे सकते हैं। आप इस्तीफा दे दें। हमारी पी.डब्लू.डी. की नालियां देख लें कि साफ हैं और वैसे हमारे पांच पार्षद चुन कर आ गये हैं तो उनमें से तीन महापौर बनाये जा सकते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है।

दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भाजपा की एक पार्षद हैं, जिनको वह गार्डन कमिटी की चेयरमैन बनाते हैं। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी ! उन्होंने तो गार्डन में ही तीन सौ गज का मकान बना दिया। क्या कमेटी का चेयरमैन बनाया कि उन्होंने गार्डन में ही तीन सौ गज का मकान बना डाला और उसमें उन्होंने जरा सी भी शर्म नहीं जताई कि अपने घर से दसवें मकान में उन्होंने दस मकान छोड़कर जो पार्क था, उसके अंदर वो तीन सौ गज का मकान खड़ा कर डाला। डिप्टी कमिशनर को इसके बारे में ज्ञात कराया गया, उसको लिखकर दिया गया, पर उस पर कोई कारवाई नहीं हो रही क्योंकि भा.ज.पा. को तो छूट मिली हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा का राज चल रहा है उनका, जो उनके मन में आ रहा है, वो कर रहे हैं और वो गार्डन कमेटी के चेयरमैन ने करके दिखाया है और दूसरे अगर मैं अपने इलाके के महापौर की बात करूं तो महापौर ने भी वो चार लोगों का खूनी है। क्योंकि असल में बिल्डिंग की बेसमेंट खोदी जाती है, जहां पर सिर्फ चौदह फुट तक खुदाई अलाउड है और उसको अठारह फुट से ज्यादा खोद दिया जाता है और साथ के मकान

की मिट्टी की दीवार जो उसके अंदर गिर जाती है, नौ के नौ मजदूर उसमें दब जाते हैं, जिसमें से पांच घायल होते हैं और चार मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं हो जाती, चार का खून कर देता है वो महापौर और फिर वही बात कि डिप्टी कमिशनर उस पर मिट्टी डलबा देता है और रातों रात उस बेसमेंट को बंद करवा देता है और लेटर लिखने पर उस पर कार्रवाई करने को बोला जाता है तो उस पर कोई कारवाई नहीं की जाती है। क्योंकि दोबारा से वही बात है कि वो भी एक भा.ज.पा. का पार्षद है। उसी राजा का एक छोटा सा वजीर है जो हमारे देश पर आज राज कर रहे हैं और इसे छोडिए और आज जुम्मे का दिन है। आज हम लोगों का रमजान का मुबारक का महीना चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले 31 मई को हमारे यहां के मस्जिद के इमाम साहब मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई, हमारे यहां पर अभी एक ट्रेडिशन हैं, जिसको कहा जाता है सब्र का एक महीना। इसमें हम लोग जाकर इबादत करते हैं कब्रिस्तान में। हमारे कब्रिस्तान का बहुत बुरा हाल है तो आप वहां पर सफाई करा दें। कब्रिस्तान का बहुत बुरा हाल होता है। डिप्टी डाइरेक्टर को बार–बार सूचित करने पर वो उसकी सफाई नहीं कराता। वहां पर हम लोग प्राईवेट गाड़ी मंगाकर, मैं उनका फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह देखिए फोटोग्राफ कि प्राईवेट गाड़ी मंगाकर हमारे कार्यकता, मैं खुद उनके साथ मिलकर वहां पर जाकर सफाई करता हूं और सफाई करने का फल हमें क्या मिलता है कि वहां के जो महापौर हैं, वो हमारे ऊपर एफ.आई.आर. करा देते हैं, जो कि वह कूड़ा उठा कर हमने ऐसे डस्टविन में फैंक दिया, ऐसे ढलाव में फैंक दिया जिसमें उन्होंने उसको इल्लीगल रूप से... बाहर कूड़ा होता

है और अंदर इन्होंने शराब पीने का अड्डा बना रखा था, यह उसकी फोटाग्राफ है, आप देख सकते हैं कि वहां के जितने भी कान्ट्रेक्ट पर लोग दिये हुए हैं वहां पर वो लोग बैठकर शराब पीते थे, इल्लीगल बिजली का कनेक्शन था। मैंने खुद जाकर उसकी इंसपेक्सन की, एस.एच.ओ. को दिखाया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुई। वही बात है अधेर नगरी, चौपट राजा। एफ. आई.आर. मेरे ऊपर कर दी गई। थाने में मुझे बुला लिया गया। तो यह राज चल रहा है जी! आप यह देख सकते हैं कि क्या अंधेर नगरी सी यह लोग राज चला रहे हैं और कल यकायक यह चिट्ठी आती है, यह तो बिल्कुल देखकर पता चल जाता है कि भ्रष्टाचार जो है, वह बिल्कुल आप कह सकते हैं कि टाप आफ द वर्ल्ड पहूंचा है एम.सी.डी. के अंदर! आज गुगल के अंदर आप सर्च करके देख लें कि टॉप करप्सन डिपार्टमेंट तो उसमें एम.सी.डी. दिखाया जाता है। सौलह नीचे बोटम्स खुलते हैं, वहां पर लिखा आता है एम.सी.डी., एम.सी.डी. और एम.सी.डी.। आज यह जो चिट्ठी आती है, यह लिखा हुआ है दिल्ली नगर निगम के बिल्डिंग के विभाग के वेस्ट जोन के चौदह करोड़पति वेलदारों के नाम। यह वेलदारों के नाम लिख कर दिये जाते हैं। हैं ये वेलदार, लेकिन यह करोड़पति हैं। इनके नाम, इनके वार्ड नंबर, इनकी पूरी डिटेल भुगती जाती है राजा भंडारी द्वारा, यह चिटठी मुझे भेजी गयी है, जिसके अंदर पूरा उन्होंने खुलासा किया है। मैं आपसे...

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड कीजिए, प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : कंक्लूड कर रहा हूं जी। कंक्लूड तो इन्होंने कर ही दिया था मेरे को एफ.आई.आर. करके जी।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री जगदीप सिंह : खैर! यह चिट्ठी भी मैं आपके पास भिजवा रहा हूं। बस आपसे यह निवेदन है कि आज जो एम.सी.डी. पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार हमारी कोई कड़ा एक्शन लेकर पूरी दिल्ली की जनता को यह दिखायें कि वाकई हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। एक ऐसा यहां से कोई अध्यादेश पास होकर जाना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई करने की न सोचें। वो बात अलग है कि इन्होंने मुझे कब्रिस्तान साफ करने से रोका था। अल्लाताला इनको साफ करेगा, पक्की बात। आठ महीने बाद, यह गारंटी की बात है। लेकिन आठ महीने भी ये लोग क्यों रहें ? आठ महीने भी इनके ऊपर कोई न कोई कड़ा रूख हमारी सरकार अपनायें। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

सदन की समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। मेरी प्रार्थना है माननीय सदस्यों से सीएम साहब ने ठीक साढे पांच बोलना है। अगला कार्यक्रम है। कही उनको जाना है। अब हम बहुत शार्ट में अपनी बात रखें। श्री सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारती : आपने मुझे इस गंभीर मुददे पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने बड़े डिटेल में एम.सी.डी. के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सदन को अवगत

कराया आपके जरिये इस मुददे को उठाने का प्रयास किया। ये जो एम. सी.डी. में व्याप्त भ्रष्टाचार है। ये क्यों है? किन कारणों से? ये आज की तारीख में अगर भा.ज.पा. और कांग्रेस के पाषर्दों की संपत्ति की तरफ हम देखें तो राजनीतिक जिंदगी में आने से पहले किसी के पास रेन्टेड प्रापर्टी थी, आज उनके पास ग्यारह ग्यारह मकान हैं किसी के पास पांच सौ करोड़ हो गया है, किसी के पास छह सौ करोड़ हो गया है किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। ये बहुत बड़ी इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों हुआ? उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई ? मैं चलता हूं, मैं अपने क्षेत्र की तरफ मेरे क्षेत्र में चार पार्षद हैं –एक हैं उनमें माननीय सतीश उपाध्याय जी जो कि दिल्ली प्रदेश भा.ज.पा. के अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ा नायाब तरीका दिल्ली में चल रहा है। हमारे कोई भी एम. एल.ए. एम.सी.डी. को कोई चिटठी लिखकर के कोई काम करने का जब प्रार्थना करता है, बताता है कि हां, काम होना चाहिये। वो काम तो हो जाता है लेकिन बोर्ड उनका लग जाता है समस्यायें लेकर के हम जाते हैं एम. सी.डी. के पास। या तो वो एम.सी.डी. काम नहीं करेगा और अगर काम करेगा तो बोर्ड उस कन्सर्न्ड पार्षद का लग जाता है और बोर्ड कैसा लगता है? सतीश उपाध्याय जी बोर्ड कैसा लगाते हैं? उस पर अपना इन्ट्रोडक्शन लिखते हैं, उस पर लिखते हैं दिल्ली प्रदेश भा.ज.पा. अध्यक्ष। वो ये नहीं लिखते कि हम वार्ड 161 के काउंसलर हैं तो धन्यवाद लेते वक्त शरमाते हैं कि अपने आप को काउंसलर कहने में अपने आपको उनको शर्म आती है। मुझे जो जानकारी है कि जो इनकी संपत्ति पहले थी, उससे कुछ नही तो आज जहां तक लोग कहते हैं जो लोकल क्षेत्र के लोग कहते हैं। ये

तो जब ए.सी.बी. हमारे पास होता, जिस तरह से आज मनीष भाई ने ये बात रखने का प्रयास किया अगर आज ए.सी.बी. होता तो इनमें से कई जेल में होते। यही तो डर है आज जो मनीष भाई का वक्तव्य इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि ए.सी.बी. आपने छीना क्यों हमसे? भ्रष्टाचार के उपर तो बात करने में बहुत मजा आता है आपको लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने आपको इन्ट्रेस्ट ही नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि आप खत्म हुए। इनको इतना समझ में आता है तो अगर आज ए.सी. बी. हमारे पास होते तो चारों पाषर्दो के खिलाफ ए.सी.बी. में केस होता और इनमें से मेरा ख्याल है चारों ही जेल में होते और उनमें से चूंकि अगर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अगर जेल चला जाये तो पूरी दिल्ली प्रदेश भा. ज.पा. जेल चली जाती है। यही तो उनको डर है। मुझे अभी चार दिन पहले एक सफाई कर्मचारी, बुजुर्ग सफाई कर्मचारी मेरे पास आई। कहा कि जी हजार रूपया मेरी तनख्वाह से काट लिया मेरे सेनेटिरी इंस्पेक्टर ने। मैंने बोला कि भई क्यों काट लिया तो कहता है कि जो तुमने छुटटी ली थी, उसको अगर हम लगा देंगें तो हजार रूपया दे देंगें आपको। हजार रूपया देने से हो जायेगा। तो मैंने उसको बुलाया। वो इतना घबराया हुआ था। चूंकि मेरे आफिस में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं। वो घबराया कि जी, अब तो सब कुछ खुल जायेगा। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन ये बताओ ये पैसा जाता कहां है? तो कहता है कि जी आपको क्या बताये? पैसा हर जगह जाता है। जहां जहां आप सोच रहे हैं वहां भी जाता है। मैंने कहा नाम बता दो। कहते, नाम बताऊंगा तो मेरी नौकरी चली जायेगी। मैंने उसको प्रेशराईज भी नहीं किया लेकिन जहां तक मुझे

समझ में आया, उसका इशारे से कहना कि जी पचास हजार रूपया महीना सैनिटरी इंस्पेक्टर वहां के काउंसलर को देता है तो ये तो भ्रष्टाचार एक तरीके से चल रहा है और ये उस क्षेत्र का सैनेटरी इंस्पेक्टर है। जहां के काउंसलर हैं माननीय श्री सतीश उपाध्याय जी। इसमें हम लोग अपनी जिंदगी जब देखते हैं तो जिस तरह हम जीते हैं और जिस तरह से भा.ज.पा. कांग्रेस नेतागण और पार्षद जीते हैं, उनकी रहनी सहनी में और हमारी रहनी सहनी को देखकर मालूम पड़ता है कि कहां पर क्या चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन चारों पाषर्दों की जिंदगी और ऐसे भा.ज.पा. कांग्रेस नेताओं की जिंदगी को व्याख्यान करने का प्रयास करें तो उसमें एक मुझे कल ही पार्क में किसी ने कहा, एक दो लाईन का सुनाया कहा कि जी, पहले के जमाने में जब ईमानदार नेता हुआ करते थे। आप लोग आने के पहले बरसों पहले तो कहते थे जी कि मुझे टिकट वहां से दो। जहां पर मैं रहता हूं क्योंकि मुझे वहां सब जानते हैं। कहते हैं जी अब भा.ज.पा. नेता कहता है कि जहां मैं रहता हूं वहां से टिकट मत दो क्योंकि मुझे यहां सब जानते हैं। अब ये इसी लाईन पर मुझे लगा कि चूंकि वहां भी मेरे क्षेत्र में जो पार्षद हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं फिर पार्षद का चुनाव लडना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, पार्षद का चुनाव भी लड़ लीजिये। लेकिन वो वहां से लडना चाहते हैं जहां वह नहीं रहते। ये तो चरितार्थ हो गया। ये जो कहावत, जो भाई ने मुझे शेयर किया मुझे ये होते दिखा चूंकि उनको वहां सब जानते हैं, इसलिये वे वहां से चुनाव लडना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने बडे तरीके से किसी ने कहा ये महा करप्ट डिपार्टमेंट है एम.सी.डी. ,

किसी ने कहा महाचोर डिपार्टमेंट है एम.सी.डी. और अगर इसको आगे ले जाये।तो मदर आफ आल करप्ट डिपार्टमेंटस सारे करप्ट डिपार्टमेंटस की माता एम.सी.डी. है और ये एम.सी.डी. करप्ट क्यों है एम.सी.डी. तो इन्स्ट्रूमेंट है एम. सी.डी. तो वैसे ही जैसे दिल्ली सरकार थी, दिल्ली सरकार में करप्शन व्याप्त था हमारे आने के पहले, आज भी है लेकिन बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. तो वो है जैसे कि घर में चाकू है और उस चाकू से किसी की गरदन काट दो या चाकू से सब्जी बना लो। अब एम. सी.डी. जिसके हाथ में रहेगी, उसका नेचर वैसा ही हो जायेगा तो आज एम.सी.डी. अगर मदर आफ आल करप्ट डिपार्टमेंटस है तो वह अपने कारण नहीं है, वहां बैठे नेताओं के कारण है। अगर भा.ज.पा. शासित एम.सी.डी. आज करप्ट कहला रही है तो ये भा.ज.पा. के पार्षदों को शर्म आनी चाहिये और शर्म से उनको डूब मरना चाहिये लेकिन ये डूब नहीं मरेंगे। ये पहले एम.सी.डी. को डूबायेंगे और उसके साथ साथ में अगले साल इनका डूबना हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कन्कलूड करिये सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : आप इनके स्कैमस को देखिये हमारे साथियों ने बड़े डिटेल में रखा है इसलिये मैं इसको नहीं रखूंगा। पेंशन स्कैम है। उसके बाद टोल स्कैम है। उसमें टोल में बताया गया है कि जब एक इन्डीपेंडेंट बाडी ने श्री राम इंस्टीटयूट ने एक स्टडी किया तो पाया कि 1900 करोड पर ईयर की अर्निंग हो सकती है और उसमें से सिर्फ 525 करोड पर ईयर पर टोल का सारा कार्यक्रम दे दिया जाये किसी को और

किसको दिया गया कहते हैं कि भा.ज.पा. के किसी बडे नेता को दिया गया तो हजार करोड़ की लोस तो वही हो गया। हजार करोड की अर्निंग हमें वहां से हो जाती।

अध्यक्ष महोदय, एडवर्टाइजमैन्ट स्कैम, प्रॉपर्टी टैक्स स्कैम और एक से एक स्कैम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके अस्पतालों के क्षेत्र में हो। ये सारे के सारे स्कैम ये बताते हैं कि जब आम आदमी पार्टी म्युनिसीपैलिटी में आयेगी तो किस तरह से इनकी फजीहत करेगी जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को विराम देने के पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो सुनते रहते है... आजकल तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी अखबार में कह दिया कि जी जो भी हम चुनाव में कहे थे, वो तो जुमला था और मनीष भाई यहां बैठे हैं उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि whatever we have promised to Delhites, we are under contractual obligation to fulfil them. इतनी हिम्मत होनी चाहिये। ये बडे गर्व की बात है हमारे सरकार ने –''कहा जो हमने चुनावी वायदे किये वो वादे नहीं हैं वो कॉट्रक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर हम उसको फुलफिल करके दिखायेगें।'' एक तरफ तो जुमलाबाजी चल रही है। उनके राष्ट्रीयध्यक्ष ने कहा दिया कि ये तो जुमले थे। क्यों विश्वास कर लेते हो ? और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जी, हम तो ड्यूटी बाउण्ड हैं। हमें तो कॉट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर इसको फुलफिल करके दिखाना है। ये बहुत बडा अंतर है और पूरा विश्व देख रहा है इसको। पूरा दुनिया देख रहा है इसको।

अध्यक्ष महोदय, करीब करीब इस बात को मानीनय नरेंद्र मोदी भी शायद सहमत हैं कि एम.सी.डी. में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप देखें उन्होंने अपनी

स्कीम में कहा कि एन.डी.एम.सी. एरिया को हम स्मार्ट सिटी बनायेगें और पूरी दिल्ली को छोड़ दिया तो जो एम.सी.डी. जिसमें कि भा.ज.पा. अभी शासन में है। भा.ज.पा. शासित एम.सी.डी. की दिल्ली में, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने नहीं सोचा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो भी जानते हैं कि एम.सी.डी. में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है! 'घोस्ट एम्पलाइज' का मामला हो, आजकल 'मच्छरदानी स्कैम' चल रहा है। मच्छरदानी वो बेच रहे हैं ब्राइब की तरह दे रहे हैं एक से एक इनके कारनामें हैं। इन कारनामों से जो एम.सी.डी. का नाम बदनाम हुआ है, इसको तो एक ही पार्टी धो सकती है। ये जब पार्टी आयेगी एम.सी.डी. के अंदर तभी ये सारे पाप और सारे एम.सी.डी. के जो इसके उपर इल्जाम लगे हैं, धुल पायेगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में चूंकि किसी ने कहा कि ट्री प्रूनिंग ये जो शमशान घाट में जो लकड़ियों का चलता है। एम.सी.डी. में कोई पालिसी नहीं है कि ट्री प्रूनिंग से जो लकडियां निकलती है, वो कहां जायेगीं ? इन लोगों ने सारा बिजनेस कर रखा है। इन्होंने शमशान घाट तक अपना बिजनेस फैला रखा है कि वो लकडियां ट्री प्रूनिंग के नाम पर इकटठा करते हैं और शमशान घाट में बेचते हैं। ये उस पैसे को भी खा जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी कापी आपको भेज दी है मैं अंत में, एक motion move करना चाहता हूं:

''motion seeking constutiton of a House Committee to inquire into alleged rampant corruption and irregularities in the Municipal

Corporsations of Delhi and to suggest measures for improvement in their functioning."

अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से जो हमारा चर्चा चल रहा है, उसके संदर्भ में this Committee is to be formed and the motion which I wish to move is the following:

"this House agrees that a House Committee be constituted to inquire into alleged rampant corruption and irregularities in the Municipal Corporations of Delhi and to suggest measures for improvement in their functioning. That the Committee shall consist of the following members."

Hon'ble Speaker, Sir, this motion which I have just stated, that motion I wish to move and this requires your kind permission. With these words, I rest this brief speech on alleged corruption of MCD and measurses therefrom. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया जी : अध्यक्ष जी , बहुत बहुत धन्यवाद। एम. सी.डी. जैसे ज्वलंत विषय पर समय देने के लिये। बेसिकली मेरे सभी साथियों ने बहुत डिटेल में और बहुत विस्तार से एम.सी.डी. के जो काम हैं, जो भ्रष्टाचार उन्होंने मचाया, उस पर बहुत डिटेल में सब कुछ बोला। जैसा कि सोमनाथ भाई ने भी कहा कि फर्क केवल इस बात का है कि आपकी नीयत कैसी है एम.सी.डी. तो एक टूल है लेकिन ये देखना पडेगा कि एम. सी.डी. को गवर्न कौन कर रहा है। कहने को तो वो बोलते हैं कि जी,

हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। राष्ट्र से बहुत मतलब है, उनको देश बहुत दिखता है लेकिन क्या जिस तरह का भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, क्या इस तरह का जो मिस मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, एम.सी.डी. में वो कहीं राष्ट्र को बनाने का काम है या राष्ट्र को लूटने का काम है। देखने की जरूरत है। कहने को तो वो कह रहे हैं कि जी हम एम.सी.डी. में शासन कर रहे हैं लेकिन वो शासन कम है, कुशासन ज्यादा है और अध्यक्ष जी, अगर उनके भ्रष्टाचार और उनके कुकर्मो की अगर बात की जाये तो लिस्ट इतनी लंबी है कि उस पर हर एक लाईन पर बात की जाये तो दो दिन का सत्र भी बहुत छोटा सत्र रखा गया है। इस पर बहुत लंबी और गहन चर्चाएं हो सकती हैं। इस विषय पर मेरा यह मानना है कि जितने भी यहां पर सदस्य बैठे हैं चाहे इस सम्मानित सदन में और जो कर्मचारी बैठे हैं और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक भी व्यक्ति आपको आज ऐसा नहीं मिलेगा जो एम. सी.डी. की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होगा। आप सब माननीय सदस्य हैं। आप अपने क्षेत्रों में रिप्रजैन्ट कर रहे हैं। आप देखेंगें कि हरेक क्षेत्र में जो सफाई की स्थिति है, जो गंदगी से पूरी दिल्ली में इस टाईम स्थिति है, वो देख के ऐसा लगता नहीं कि है कोई सफाई के लिये या इस काम के लिये भी कोई ऐजेंसी यहां पर दिल्ली में काम कर रही है।

खासकर जमना पार की स्थिति है,जमना पार से आप खुद रिप्रजैन्ट करते हैं। जमना पार के क्षेत्र को वहां जाकर देखेगें तो जो स्थिति है, वहां पर जगह जगह कूडे के ढेर लगे हए हैं। जगह जगह नालियां भरी हुई है, जगह जगह स्थिति इतनी खराब है कि रहने के लायक जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है इस सबका ये नतीजा है कि दिल्ली

पूरे कूड़े के ढ़ेर में तब्दील हो गई है और इसके लिये अगर कोई जिम्मेवार है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं केवल और केवल भा.ज.पा. जिम्मेवार है क्योंकि पिछले दस साल से जिस तरीके से उन्होंने इस पर कब्जा करके और एम.सी.डी. को फाइनेंशयली खोखला कर दिया है बिल्कुल, पूरा पैसा जो लोगों की भलाई के लिये यूज होना चाहिये था, वो पूरे भ्रष्टाचार के थ्रू उसमें मिस–मैनेजमेंट के थ्रू सारा पैसा एक तरीके से उन्होंने चूस लिया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग ना तो पेंशन ले पा रहे हैं और ना कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे हैं। कोई भी काम जो जनता की भलाई के लिये होना चाहिये, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे।

सफाई के मुददे पर कुछ आंकडों के माध्यम से भी सदन का ध्यान चाहूंगा। मेरी विधानसभा का उदाहरण ले लीजिये, बहुत छोटी सी विधानसभा है, छह सात किलोमीटर का एरिया है। उसमें 327 कर्मचारी एम.सी.डी. की तरफ से डिप्लाय हैं लेकिन आप पूरे क्षेत्र में कहीं घूम लीजिये, आपको एक कर्मचारी नहीं दिखाई देगा। कभी भी आप सुबह चले, जाइये शाम को चले जाइये, किसी भी टाईम 327 कर्मचारियों में से एक भी आपको नजर नहीं आयेगा और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। इसमें सफाई कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। पूरा का पूरा वहां पर जो इन्होंने एक सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ठेकेदार, वहां का लोकल काउंसलर पूरी तरह से एक सिस्टम है कि जी, सुबह आओ, हाजिरी लगाओ और चले जाओ। कर्मचारियों से बात होती है, वो कहते हैं कि जी, हम काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन एम.सी.डी. में सिस्टम ही ऐसा है जी। कोई ईमानदारी से काम नहीं कर

सकता। कोई भी कर्मचारी ये कहे कि मैं काम करना चाहता हूं, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बस, आप हाजरी लगाओ और चले जाओ। स्थिति इतनी खराब है कि ना केवल वो एम.सी.डी. के खजाने को लूट रहे हैं बल्कि कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं। जिस गरीब तबके से सफाई कर्मचारी आता है, जिस निचले तबके से वो लोग आते हैं, बड़े शर्म का विषय है कि उनका भी बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। स्थिति ये है कि कोई कर्मचारी किसी बात पर अगर बात रखना चाहे कि मेरे को पैसे ठीक से नहीं मिल रहे या कुछ तो डायरेक्ट उसको सीधे–सीधे नौकरी से निकालने की धमकी दे देते हैं कि आपको हम काम पर नहीं रखेंगे अगर आप हमारे करप्शन के सिस्टम में अगर काम नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में अगर ये ऐसा सब कुछ चल रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर सारे सदन का ध्यान एक बार जरूर जाना चाहिए और कुछ न कुछ हमें इस विषय पर सोचना चाहिए कि ये जितना भ्रष्टाचार इस एम.सी.डी. में चल रहा है, वो किस तरीके से रूक पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो कूड़ा डालने के लिए हमारे यहां खत्तों का निर्माण किया गया है... आप पूरी दिल्ली में देखिए कि एक भी कूड़े डालने की जगह पर कूड़ा खत्तों के अंदर नहीं मिलेगा। जहां पर भी आप देखें वो सारे खत्तों के बाहर ही कूड़ा डालते हैं और खत्तों का यूज किसलिए हो रहा है? खत्तों का यूज हो रहा है केवल एड लगाने के लिए। केवल ये हो रहा है कि उस पर एड लगा दो और उससे पैसा कमा लो। कूड़ा जो भी है, वो सब रोड पर है। इससे

ये एक बात और समझ में आती है कि एम.सी.डी. की प्रॉयरिटी सफाई नहीं है, उनकी प्रॉयरिटी ये नहीं है कि कूड़ा अंदर रहे, उनकी प्रॉयरिटी ये है कि पैसा कहां से कमाया जा सकता है, मोटा माल कहां से आ सकता है, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि सफाई हो।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप कंपैरिजन कीजिए पॉश एरियाज में और जो थोड़ा सा कंपरैटिवली जहां मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के परिवार रहते है। मान लीजिए, अनअथोराइज्ड़ कालोनी हैं, जै.जै.कलस्टर हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, जिस कांस्टिट्युएन्सी में ऐसा है, वहां पर सफाई कर्मचारियों की संख्या अपने आप कम है जब कि वहां पर सफाई कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। आप पॉश कालोनीज की बात करेंगे तो वहां पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये दिखाता है कि भा.ज.पा. की जो गरीब विरोधी मानसिकता है, ये उसको दिखाता है। ये चाहते हैं कि केवल अमीर लोगों के घर पर थोड़ा बहुत काम हो जाए, गरीबों के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिन–जिन एरियाज में चाहे वो अनअथोराइज्ड़ कालोनी हों, कलस्टर हों, झुग्गी बस्तियां हों, वहां पर सफाई कर्मचारियों की ज्यादा डिपलायमेंट होनी चाहिए क्योंकि वहां पर सफाई की ज्यादा आवश्यकता है। इसी डिफरेंस को अगर हम, जो हमारी पार्टी का मोटो रहा है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी चिंता सबसे पहले होनी चाहिए। उसकी केयर के बारे में, उसके विषय में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। जब कि हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। ये दिखा रहा है कि भा.ज.पा. केवल अमीर लोगों का ध्यान रखती है, अमीर लोगों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है, गरीबों का विरोध करती है! इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूरी दिल्ली के मुसलमानों की तरफ से शिक्षा मंत्री श्री मनीष जी और मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से 1995 के बाद में दिल्ली के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल में एक भी उर्दू टीचर की भर्ती नहीं हुई, तो आज ये जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर 1100 सरकारी स्कूलों में और जो साढ़े तीन सौ, तीन सौ सत्तर के करीब जो उर्दू टीचर की कमी थी, आज उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है जो ये दिखाता है कि ये सरकार सबके साथ है। ये जाति के नाम पर काम नहीं करती, मजहब के नाम पर काम नहीं करती, गरीब के नाम पर काम नहीं करती, अमीर के नाम पर काम नहीं करती, जाहिर सी बात है कि उर्दू टीचर की अगर पूरी दिल्ली के अंदर भर्ती नहीं हुई तो जरूर जाहिर सी बात है कोई न कोई मानसिकता की कमी रही होगी या कोई न कोई भेदभाव जरूर हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज एम.सी.डी. पर बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से दिनेश मोहनिया जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि एम.सी.डी. भेदभाव करती है क्योंकि एम.सी.डी. पर इस वक्त जो कब्जा है, वो बी.जे.पी. का कब्जा है और बी.जे.पी. दलित विरोधी, गरीब विरोधी, मुस्लिम विरोधी, पिछड़ा विरोधी – इन सारी नीतियों के साथ काम करती है। मेरी विधान सभा में ये सारी चीजें होती हैं। मेरी विधान सभा में एक सरिता विहार वार्ड है, पूरी विधान सभा में मेरे 600 के करीब सफाई कर्मचारी

हैं। सरिता विहार वार्ड में, एक सरिता विहार है जिसमें तकरीबन 17,000 वोटर हैं उसके अंदर 250 सफाई कर्मचारी हैं। उसी के बिल्कुल बराबर में शाहीन बाग है जिसके अंदर 29,000 वोटर हैं वहां पर 6 सफाई कर्मचारी हैं। 17,000 वोटर पर 250 सफाई कर्मचारी और 29,000 वोटर पर 6 सफाई कर्मचारी। उसी के आगे एक जे.जे.कालोनी है जिसमें तकरीबन 50,000 वोटर हैं, वहां पर 60 सफाई कर्मचारी हैं तो ये बिल्कुल साफ सी बात है कि ये जो एम.सी.डी. है, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करना चाहती है। हम ये नहीं कहते कि आपने सरिता विहार के अंदर ज्यादा सफाई कर्मचारी रखें। वहां पर आपने जरूरत के एतबार से रखे होंगे क्योंकि वहां पर कहीं भी अगर हम जाएं तो किसी सड़क पर कभी कोई धूल तक नजर नहीं आती, कूड़ा नजर नहीं आता, मिट्टी नजर नहीं आती जैसे ही आप सरिता विहार से निकल कर मदनपुर खादर की तरफ आते हो तो आपको कूड़े के अंबार नजर आ जाते है। उसकी तरफ से आप जे.जे.कालोनी की तरफ आते हो तो वहां पर आपको गदंगी, वहां नालियों के अंदर कीचड़, वहां पर बदबू, कूड़े के ढ़ेर, वो सारी चीजें नजर आ जाती है। उसके बाद जब आप मुस्लिम कालोनी शाहिन बाग के अंदर आते हो तो 6 सफाई कर्मचारी हैं, तकरीबन डेढ़ लाख की आबादी हैं और 30,000 से ज्यादा वोटर हैं, 6 सफाई कर्मचारी जो कभी सफाई नहीं करते। पीछे रजमान का महीना चल रहा है, पाक साफ महीना है। लोगों की ये इल्तज़ा होती है, लोगों की रिकवेस्ट होती है कि रमज़ान के महीनों में सड़के साफ हों, गलियां साफ हों। सबको नमाज़ पढ़ने जाना होता है। लोग वहां से गुजर कर जाते है। नालियों में कीचड़ भरी होने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से लोगों के कपड़े नापाक

हो जाते है और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाते। मस्जिदों के अंदर अब से पहले ये होता था कि रमजान के महीनों में मस्जिदों के आगे सफाई होती थी, वहां पर चूना डलता था, सफाई रखी जाती थी लेकिन आज की हालत ये है कि एक भी सफाई कर्मचारी पूरे रमजान में कहीं नजर नहीं आया। तो पीछे रमजान से कुछ दिन पहले लोग मेरे पास आए तो मैंने तकरीबन 40 सफाई कर्मचारी, पिछले एक महीने से हम लोग सफाई कर रहे हैं और अभी तक किसी भी एम.सी.डी. के एक कर्मचारी को या किसी एक अधिकारी को शर्म नहीं आई या कॉउंसलर को शर्म नहीं आई कि हम किसी मस्जिद के सामने सफाई करा दें। तो ये एक हालात है!

अध्यक्ष महोदय, हम स्कूलों की अगर बात करें, दिल्ली सरकार आज स्कूलों पर काम कर रही है। आज प्राइमरी स्कूल एम.सी.डी. के पास हैं। उनके हालात हम सबको मालूम हैं। उन स्कूलों में सफाई तक नहीं हो सकती। पढ़ाई का क्या हाल है? हम सब जानते है। अब दिल्ली सरकार जूनियर स्कूलों के अंदर, जूनियर सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के अंदर आज एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और उसका एक नतीजा ये भी है कि एक साल के अंदर हम लोगों का दो परसेंट ज्यादा, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों से ज्यादा हम लोगों का रिजल्ट भी रहा है। तो हम लोग सुधार की तरफ जा रहे हैं लेकिन एम.सी.डी. के जो स्कूल है, उनकी दशा बहुत खराब है। एम.सी.डी. का कोई भी काम है, वो ठीक से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आप इनकी डिस्पेंसरी का अगर हाल देखे तो डिस्पेंसरी के अंदर जो मरीज जाते हैं, उनकी दुर्दशा आप देखें। उनको वक्त पर देखने

वाला कोई नहीं है। डाक्टर उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर डाक्टर देख भी लेता है तो उनको दवाई देने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पास दवाई मौजूद नहीं है।

अगर आप एम.सी.डी. की सड़के देखें, मेरी विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पिछले दो साल से काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने वहां पर परमीशन ली इनसे और दस करोड़ साठ लाख रूपए जमा किया। एक साल पहले भी ये क्वेश्चन मैंने विधान सभा में उठाया था। अब फिर मैं उठा रहा हूं पिछले दो साल से, हम लोगों को डेढ़ साल से ज्यादा सड़कों को बनाए हुए हो गया, हम लोगों से डेढ़ साल से ज्यादा, इन लोगों ने हमसे पैसे भी ले लिए लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने काम अपना कर दिया, जल बोर्ड ने काम कर दिया, एक भी सड़क पर एम.सी.डी. अभी तक काम नहीं कर सकी। पैसे हमसे ले लिए, लोग परेशान है, बुरा हाल है लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है।

एम.सी.डी. जिस हालत में आज दिल्ली के अंदर है, उससे आज पूरी दिल्ली के हालात खराब हैं। खासकर अनअथोराइज्ड कालोनियों के अगर आज हालात खराब है तो एम.सी.डी. ने किया। एम.सी.डी. की जिम्मेदारी बनती थी कि अनअथोराइज्ड कालोनियां हों या अथोराइज्ड या गांव जो हैं अनअथोराइज्ड रैगुलाइज या गांव उनके अंदर जो भी नक्शे पास होने थे, इनको करने चाहिए थे लेकिन दिल्ली के अंदर एक आदमी 20 साल से मकान में रह रहा है, अगर उसको जरूरत पड़ी अपने मकान को तोड़कर बनाने की, वो बनाने पर आता है, नक्शा पास करने के लिए इनके पास

देता है तो नक्शा पास नहीं करते। सालों लग जाते है इनको नक्शा पास करने में, वो ऐसे ही इल्लीगल उसको बनाता है अगर ये लोग उसका नक्शा पास करते तो अनअथोराइज्ड पार्किंग नहीं होती, अनअथोराइज्ड दुकानें नहीं होती, चार–चार, पांच–पांच मंजिल बल्डिंगें नही बनती और दिल्ली की हालत ये नहीं होती जो आज है। मैं तो ये कहता हूं कि जो अनअथोराइज्ड कालोनी हैं, उनके अंदर भी नक्शा पास होना चाहिए जिसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन रूकेगा, छज्जे बाहर नहीं आएंगे, पांच–पांच छः–छः मंजिलें नहीं बनेगी और इलाके की दुर्दशा कम होगी। लेकिन आज क्या होता है कि नक्शे पास नहीं होते। अपनी मर्जी से आदमी बनाता है। अगर वो नक्शा पास भी कराना चाहता है तो उसका नक्शा पास नहीं होता जिसकी वजह से सरकार के पास रैवन्यू कम जाता है। अगर रैवन्यू कम जाने की वजह से आज एम.सी.डी. के हालात आप देखे तो अगर ये सिर्फ कालोनियों के नक्शे पास करना शुरू कर दें। तो इन पर जो आज रैवन्यू की कमी हैं, वो भी पूरी हो जाएगी और जो आज इलाके की, कालोनियों की दुर्दशा है, वो भी कम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री वेद प्रकाश जी। श्री अजेश यादव जी।

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एम.सी.डी. के भ्रष्टाचार के विषय में बोलने का मौका दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अब से पहले जो विषय उठाने थे, ज्यादातर आ ही चुके हैं। आज तो हालत ये

हो गई है कि अगर कोई पड़ोसी भी बेईमान है या कहीं भी कोई बेईमानी करता है, चोरी करता है तो ये कहना शुरू कर दिया है कि इसने तो एम.सी.डी. को भी मात कर दिया। मतलब एम.सी.डी. की ये पोजीशन है कि कोई इज्जत से देखता ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि चुनाव से पहले जो अभी एम.सी.डी. के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही अगर इनके ऊपर लगाम कस दी जाए तो बहुत अच्छा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं सबसे पहले तो इस सदन के अंदर निर्वाचित हमारी डिप्टी स्पीकर साहिबा राखी बिड़ला को बधाई देता हूं कि आज ये निर्वाचित हुई है और जन्मदिन की भी इनको बहुत–बहुत शुभकामनाएं और एक शोक संवेदना भी प्रकट करता हूं कि हमारे माननीय मैम्बर संजीव झा के पिताजी गुजर गए थे तो उनके लिए भी मैं दुख प्रकट कर रहा हूं और दो हमारे सदस्य जो अभी नवदांपत्य जीवन के अंदर बंधे है– सरिता जी को और अखिलेश त्रिपाठी जी को भी बधाई देता हूं।

अध्यक्ष जी, एम.सी.डी. के मसले पर बोलने के लिए साथियों ने बहुत कुछ कहा। ये आप भी जानते हो और जग जाहिर भी है लेकिन जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उनकी संवेदना देखिए कैसी, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से कह रहा हूं अध्यक्ष जी ये–

"ना करो कुछ काम ऐसा दिन के उजाले में,
कि ना चैन से सो सको रात के अंधेरे में।
ना करो कुछ काम ऐसा रात के अंधेरे में,
इस तरह मुंह छिपाते फिरो दिन के उजाले में।"

क्या देख रहे है हम इनको, मुंह छिपाते हुए फिर रहे है, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते है, ये लुका–छिपी का खेल अच्छा नहीं लगता है। जनता ने चुन के भेजा है तो टिक के बैठो और उसके ऊपर संवाद करो, बातचीत करो जो भी अच्छा लगे। क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, एक उम्मीद के साथ भेजा है। वैसे तो सच्ची बात है ये, पीछे एक पत्रकार पूछने लगे महेंद्र भाई दिल्ली के अंदर 70 सीटें थी और 67 आ गई, अरविंद जी ने कमाल कर दिया! ये तीन कैसे रह गई? तो उस समय मैंने एक जवाब दिया था झाड़ू को कितनी भी कस के लगा लो, कितनी भी करड़ी लगा लो कुछ न कुछ तो कूड़ा रह ही जाता है। जो ये तीन के प्रति दिखा रहे हैं, एम.सी.डी. को सफाई के लिए छोड़ा है, नहीं कर रहें, मैं आपके इसी सदन के अंदर एफिडेफिट दे सकता हूं जितना सफाई के नाम पर ये पैसा लेते है, सत्तर परसेंट पैसे के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली का ठेका लेता हूं, इससे ज्यादा साफ–सुथरी और डबल सफाई करके दूंगा।

अभी किशनगढ़ का एक पार्क था। एक पांच साल की बच्ची पार्क के अंदर खेलने के लिए गई थी। वह वहॉ गड्डे के अंदर गिर गई और उसकी मौत हो गई। उस मां के लिए, बाप के लिए कितनी दुखदायी घटना होगी!

लेकिन इन बेशर्मों को कही पर शर्म नहीं इस बात की। ये संवेदना प्रकट होनी चाहिए, काम करना चाहिए और कितने ही बुजुर्गों की टांगे टूटी हैं, सिर में चोट लगी है, क्योंकि जो एम.सी.डी. के पार्क हैं, उनके जाकर हालात देखें आप, जगह–जगह गड्डे पड़े हैं, कहीं पर ट्रक नहीं बना हुआ। मेरी माताएं–बहनें, बुजुर्गों का कितना बुरा हाल होता होगा, आप इसे देख सकते है।

अध्यक्ष जी, अभी कोई पेंशन चोर बैठता है इनमें कि विकलांगों की पेंशन खा जाते है। कोई इनको कहता है कि बुजुर्गों की पेंशन खा जाते है और पेन्शन चोर, पेंशन चोर! ये तो इनके लिए चोरी की कितनी भी बात कह ले कोई वो नहीं है। क्योंकि इनको शर्म नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कुछ दिल्ली सरकार के भी और एम.सी.डी. के भी काम गिनवाना चाहता हूं। इन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पास किया हमारे मुख्यमंत्री

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः महेंद्र जी, संक्षेप में रखिए।

श्री महेन्द्र गोयलः अध्यक्ष जी, संक्षेप में ही है बहुत। दिल्ली सरकार जो काम करती है जितने भी मेन्यूफैस्टो के अंदर काम लिखे तो उनको पूरा करने का काम किया और एम.सी.डी. के जितने भी काम है, कहीं पर वो काम नहीं हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सबसे पहला जो काम किया पानी के बिलों को माफ करने का काम किया और बिजली के जितने भी बिल थे, उसको माफ करने का काम किया, ये दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने का काम किया और इन लोगों ने क्या

किया कि ए.सी.बी. को छीनने का काम किया। ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात करते हैं तो बैठिए आज से पहली बार मैंने हमारे मुख्यमंत्री साहब को इस गुस्से के अंदर देखा था कि जिस हिसाब से वो भ्रष्टाचार पर बात करने की बात कर रहे थे तो उन्होंनें बिल्कुल सही कहा था कि ए.सी.बी. एक बार दे दो, एक महीने के अंदर पूरा का पूरा सफाया करके दिखा देंगे ये बिल्कुल सत्य कहा था।

दिल्ली सरकार अस्पतालों के अंदर दवाई फ्री देने का काम कर रही है, ऐलिवेटिड रोड बनाए तो उसके अंदर से पैसा बचाकर अस्पतालों में दवाई दी है, ये दिल्ली सरकार ने काम किया है। एम.सी.डी. के जितने फलाईओवर हैं कहीं पर बने है, जिनके अंदर तीन साल का समय था, सात–आठ साल हो गए, आज तक नहीं बने। बहुत से फलाईओवर्स के अंदर डबल से ज्यादा कीमत इन लोगों ने ले ली फिर भी आज तक पूरे नहीं हुए और आने वाले चुनाव तक भी वो पूरे नहीं होंगे।

एक हम लोगों ने कहा था इनको कि एम.सी.डी. जो भी पेंशन दे रही हैं, उसके अंदर दिल्ली सरकार की भी पेंशन जा रही है और एम.सी.डी. की भी पेंशन जा रही है जो तथ्यों पर आधारित है, 3583 पेंशन ऐसी थी जो अब कटी हैं। एक तरफ से दिल्ली सरकार भी उन लोगों को पेंशन दे रही थी और ये एम.सी.डी. वाले भी दे रहे थे और बहुत सी जब जांच करवाई तो 40–40, 45–45 साल के व्यक्तियों को पेंशन लगाने का काम किया है तो इन कोउंसलरों ने काम किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, ये काम होने चाहिए। सीबीआई

का एक सर्च अभियान चला था जिसके अंदर झूठे मृत्यु प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र मिले हैं, इनका ये काम है और नगर निगम के एक रजिस्ट्रार थे जिनके घर से 26 लाख रूपए कैश बरामद किए ये 22 जून, 2015 की घटना है।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः सर, कन्क्लूड ही कर रहा हूं क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ कह चुके और सिर्फ एक जो एप चला था स्वच्छ अभियान का उन दस दिनों के अंदर 38,000 शिकायतें आईं। जिसके अंदर इन्होंने पचास परसेंट भी शिकायतों का समाधान नहीं किया है। ये मैं आपके नालेज में ला रहा हूं। बहुत ज्यादा ना कहते हुए उनके लिए एक और बात कहूंगाः

"काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें,

ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें।"

जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः कर्नल सहरावत जी। संक्षेप में रखिएगा बहुत, प्लीज।

अध्यक्ष महोदयः कर्नल सहरावत।

श्री देवेन्द्र सहरावतः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

''देखने जब निकले कि क्या सूरते हाल है?

तो हर पत्ते ने किया बयां जड़ तक सब बदहाल है''

जब चुनकर विधायक बनकर आए तो बिजवासन का जो फलाइओवर देखा जिसके बारे में दो दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार में लिखा, 6 साल में प्रगति हुई नहीं थी, फ्लाईओवर आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिख रही थी और जो साथी जो इस तरफ से आए हों, जिन्होंने रानी झांसी रोड को आज इस्तेमाल किया हो तो वो देख सकते हैं कि तीन किलोमीटर रोड पे आज भी जो है आपको वाइपर लगा के चलना पड़ता है, इतनी धूल उड़ रही है और उस फ्लाईओवर को बनने में शायद वर्ष और लग जाए! ऐसी हाल थी उस हालत में जब काम करने की कोशिश करी तो बोला ''ना करेंगे ना करने देंगे, एम.सी.डी. में घुसने नहीं देंगे'' विधायक के लिए कोई जगह नहीं है एम.सी.डी. में काम करने के लिए तो आई.आई. टी. के फर्स्ट बैच के एक सिविल इंजिनियर को लार्सन एंड टूब्रो से बुलवाया, उस वर्क की स्टडी करवाई, उसमें कहा था, रूकावटे थी। वो सारी आइडेंटिफाई करवाई, 7 साल हो गये थे। अभी तक भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था, उस भूमि अधिग्रहण को डिवीजनल कमिश्नर से मिलकर पूरा करवाया, तो ये जो है कॉंट्रैक्टर को लेकर सिविल इंजिनियर को लेकर और रेलवे को लेकर जो ऊपर से ब्रिज बना रही थी, सबकी मिटिंग करवाई और आज वो फ्लाईओवर बनने को है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो अखबार में लिख तो दिया कि बहुत बुरी हालत है। लिखने वाले ने बस स्याही से लिख रखा है हमने तो ऐड़ी–चोटी से रोंद रोंद के इनको परखा है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि क्यों नहीं बना फ्लाईओवर... लेकिन कैसे बना आखिर ये नहीं लिखा और हमें, मेरे ख्याल से एम.सी.डी. के मामले में उसी दिशा में जाना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है मुख्यमंत्री महोदय से और आपसे भी कि हम इस

चीज पर भी एग्जामिन करें कि म्युनिसिपल फंक्शंज, म्युनिसिपल एक्टस में कॉर्पोरेशन को कितनी दिये जाने चाहिए आज की हालत में। आप देखिए प्राइमरी एजुकेशन हमने जो है एम.सी.डी. को दे रखा है, मेरे एक एम.सी. डी. स्कूल में एक बच्चा सीवर में डूब कर मर गया, इससे अधिक दर्दनाक और खतरनाक मौत हो नहीं सकती। मैं हाईकोर्ट में गया और मेरे पास एम. सी.डी. की डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया था, वहां पर आने की बात तो छोडिए, उस मौका– ए– स्थल पर आने की बजाए उन्होंने अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया, मैंने कहा, ''उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए।'' दिल्ली सरकार एक तरफ से स्कूलों की शिक्षा में इतनी बढ़ोत्तरी कर रही है, जो निर्माण हम करवा रहे हैं, उसमें और साथ में जो स्कूल बन रहा है, उसमें बहुत फर्क है। एक डुप्लीकेशन हो रही है, तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ जोड़ दी जाएं? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, कि हम इस पूरे सिचुएशन को हम इसकी एनलाइसिस सही करें कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है, जाना किस दिशा में है, हमें इस पूरी एक्सरसाईज को इस दिशा में लेकर जाना चाहिए कि म्यूनिसिपल फंक्शंसज क्या हैं और कितने उनके दिये जाने चाहिए और दूसरी मेरी बात है, नालियों की बात तो हमने कर ली। लेकिन आप मोटी–मोटी बात देखिए तीनों एम.सी.डी. में जैसे आज हमारे साथी ने पहले भी ये प्वाइंट उठाया था कि वेस्ट मैनेजमैंट का कॉण्ट्रेक्ट हो रहा है, ये वेस्ट मैनेजमैंट का कॉण्ट्रेक्ट 10 साल के लिए है, इसमें टोटल अमाउंट 400 से 500 करोड़ इन्वॉल्वड है और इसके जो टैण्डरिंग टर्म्स हैं, ये मेरे पास सारे कागज हैं, उसमें ये बिल्कुल क्लीयर है कि जो कम्पनी एक बार कहीं

पर भी ब्लैक लिस्ट हो रखी है, वो कम्पनी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। ब्लैक लिस्टेड कंपनी इस टैंडर में हिस्सा नहीं ले सकती है लेकिन हो वही रहा है। एक कम्पनी जो कि ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, वो कम्पनी आइ.एंड.एल.एफ.एस., वो इसमें हिस्सा ले रही है, ये कम्पनी गवर्नमेन्ट ऑफ कर्नाटका के एक कॉन्ट्रेक्ट में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है इसके अलावा ये कम्पनी, रेल विकास निगम के एक ओर टैंडर में भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। इसके अलावा इसको मैंने जब स्टडी किया तो इसमें एक ओर कंडीशन है कि एक कम्पनी एक जोन से अधिक जोन नहीं ले सकती है। ये सेफ्टी स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई फोर्स मेजर हो जाए, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें की वो कॉण्ट्रेक्ट फेल हो जाए तो एक से अधिक जोन प्रभावित ना हों, ये कम्पनी एक जोन लेने के बाद फिर दुबारा आगे एक ओर कॉण्ट्रेक्ट ले रही है – ये एक बात है। और अगर मैं पिटारा खोलूं तो मेरी विधान सभा में अगर आप एयरपोर्ट के इलाके में गये हैं तो वहां पर बहुत सारी वाटिकाएं हैं, बहुत सारे शादी स्थल है और उसमें जो है, सर्दी के मौसम में आप धौला कुआँ से लेकर गुड़गांव तक पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है। मैंने कहा कि जरा चैक तो करें कि कितनी ऑथराईज वाटिकाएं हैं? जब आर.टी.आई. लगाई और निकाला तो महज 5 वाटिकाएं ऐसी हैं, जो कि अधिकृत है, जिनकी परमिशन ले रखी है बाकी सब ईल्लीगल है यानि 250 से 300 वाटिकाएं इल्लीगल फंक्शन करती हैं, एक शादी में पांच लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का भाड़ा लिया जाता है, यानि एक शादी के सीजन में लगभग 500 करोड़ का इल्लीगल ट्रांजैक्शन होता है, जो पिछले एक दशक से हो रहा है और इसमें पूरा

चूना सरकार को लग रहा है और गरीब आदमी ये पैसे दे रहा है, जानबूझकर उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदयः सहरावत जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री देवेन्द्र सहरावतः अध्यक्ष महोदय,मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस मैग्नीटयूड पर, किस हालत में, किस तरह से मिलकर पूरा सिस्टम लोगों को, सरकार को और हमारी ट्रेजरी को किसी प्रकार से लूट रहा है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन 29/06/11 का एक पत्र है, 77 करोड़, 98 लाख 77, 50 हजार 503 रूपये, ये गेन है जो खाली ड्रेन नम्बर–2 दिलशाद गार्डन मैट्रो स्टेशन के पास शुरू होती है, और 2011 से आज 2016 शुरू हो गया, ये एक बहुत बड़ा घोटाला एनडीएमसी का है, आज तक इसमें कोई काम नहीं किया गया। सर, इसके अंदर सारी धूल दिलशाद गार्डन मैट्रो से लोग उतरते हैं, आगे अगर आप चले जाइये तो कितनी धूल उड़ती है, वहां पर कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, और जो इसमें दोषी अधिकारी हों एन.डी.एम.सी. के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों के जन मानस के स्वार्थ से भी जुड़ा हुआ सवाल है कि आज तक 2011 से लेकर 2016 तक एन.डी.एम.सी. ने इस पर काम क्यों नहीं किया? ये मेरा आपसे आग्रह है, इसकी जांच कराई जाए और जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये... एक मिनट

सर, मैं अपनी बात कहकर खत्म करता हूं कि आज मुझे अपने जीवन में बड़ा दुख हुआ है, रमजान का महीना चल रहा है। आज मुझे वहां के डी.सी. के पास चार्ज था, आज उसको ये कहना पड़ा रात को साढ़े 11 बजे मेरे पास फोन आया बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क से कि वहां पर लोग रमजान के लिए जाते हैं और जो ढलाव है, उसका सारा कूड़ा उस रोड के ऊपर है वहां पर, हजारों लोग वहां से गुजरते हैं, कई दिन से हम लोग एम.सी.डी. के लोगों से इस बारे में बातचीत कर रहे थे, कोई उत्तर नहीं मिला। आज मुझे कहना पड़ा कि अगर ये आज मैं सुबह पहुंच रहा हूं। ये कूड़ा अगर आज नहीं उठा तो वहीं धरने पर बैठूंगा। तब जाके सुबह 10 बजे वहां से कूड़ा हटाया गया, हमारे यहां के पूर्व मंत्री ने, पूर्व विधायक ने गांधी नगर विधान सभा में दो ढ़लाव बेच दिये मिलके। आज पूरी गांधी नगर... एशिया की बिगेस्ट मार्किट है, मार्किट के बीच में गांधी नगर थाने के पास ढलाव है, कितने व्यापारी हमारे यहां बाहर से आते हैं लेकिन कुछ भी वहां कहने वाला नहीं है। मैं इस संबंध में पहले भी ये बात उठा चुका था लेकिन हमारे यहां के प्रतिपक्ष के नेता हैं वो और कॉग्रेस व बी.जे.पी. के लोग, दोनों उसके अंदर मिले हुए हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो पूर्व विधायक के खिलाफ बहुत कुछ मामला आप लोगों के सामने आ जाएगा, आपका बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर दो दिन से चर्चा हो रही है, पर व्यक्तिगत तौर पे हमारे जिन विधायकों ने अपनी विधान सभा के अंदर जो जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ,वो मुद्दे यहां पर उठाए हैं या दिल्ली से संबंधित भ्रष्टाचार का मुद्दा

यहां उठाया है, उसकी कम से कम नगर निगम के अधिकारियों की जवाब देही तय हो।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी ने अभी एक प्रस्ताव रखा है, उस पर अभी करेंगे चर्चा।

श्री शरद चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक आर.टी.आई. लगाई अभी एम.सी.डी. में कि ये कितनी फैक्ट्रियॉ सील करते हैं या मकान या दुकान सील करते हैं तो क्या उनकी सील खोलने की प्रक्रिया हो जाती है? किसी की नहीं होती। फिर मैंने अपना सर्वे कराया कि मैं पता करूं कि जो सील हुई थीं, वो सील्ड हैं या उनमें काम हो रहा है, पता लगा उनमें एक भी सील्ड नहीं है। उन सबमें काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? पूरी की पूरी मंथली चल रही है, आज हम सफाई कर्मचारियों को दोष देने बैठे हैं। मैं भी सुन रहा हूं सारी। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उन सफाई कर्मचारियों की मजबूरी क्या है? क्योंकि जो पार्षद बैठा है, जो सिस्टम में बैठा है, उनको उनके लिए कमाना पड़ता है, उनके लिए काम करते हैं। मनीष जी ने दौरे किये स्कूलों के। तो मैंने वहां पर सफाई करवाई स्कूलों की। कूड़ा इतना इकट्ठा हो गया। अब मैंने पार्षद से बोला की सफाई कर्मचारियों को बोलें की कूड़ा उठाए वहां से, अब गाड़ियॉ तो उन्हीं के पास है, हमारे पास तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम कूड़ा उठा लेंगे। पार्षद क्या कहते हैं इंस्पेक्टर से वहां से कि अपना ट्रांस्फर करा लेना कल अगर वहां से कूड़ा उठ गया तो। उनके साथ भी बहुत सी मजबूरियॉ जुड़ जाती हैं कई बार, और एक और है –ये जो होर्डिंग लगती है सड़कों पर, ये एम.सी.डी. के पास है।

उसमें डायरेक्टर मेरा जानने वाला आ गया। मैंने उनसे पूछा कि होर्डिगों का क्या चार्ज है? कहता है, ''होता क्या है? टैंडर दो होर्डिगों के करा लिए, पोल खड़े कर दिये दस...

अध्यक्ष महोदयः ये विषय आ चुका है, आपका 280 आ चुका है, उसमें आ चुका है। बैठिए–बैठिए प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलना है बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछले दो दिन से नगर निगम के काम–काज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले अखबारों में में ये अनाउंसमैंट हुई थी कि दिल्ली विधान सभा नगर निगम के कामकाज पे चर्चा करेगी। इस खबर से इतना बवाल मच गया इन लोगों के दिल में कि पता नहीं, ऐसा क्या जाएगा इन्होंने सारे अपने काउंसलर लगा दिये, धरने कर दिये, प्रदर्शन मेरे घर पर, मनीष के घर पर, आप सभी लोगों के घरों पर भी आए होंगे, बता रहे हैं, सारे विधायकों के घर पर इनके काउंसलर धरने करने लगे! ऐसा क्या हो गया भई। अच्छा काम कर रहे हो तो तारीफ करने के लिए तो सैशन बुलाया है, अच्छी तुम्हारी तारीफ करेंगे। अच्छा काम किया है तो चोर की दाढी में तिनका, उनको पता था कि अगर दो दिन का विधान सभा का सैशन होगा तो उसके अंदर सारा सच आने वाला है और इनको खूब गालियॉ पड़ने वाली हैं तो उसके पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया, तीनों नगर निगम का ज्वाइंट सैशन होगा, कौन से कानून में होगा ज्वाइंट सैशन ? तीनों अलग–अलग नगर निगम है, तीन अलग–अलग कानून बन चुके हैं। ज्वाइंट सैशन किस चीज का होगा? तो बुरी तरह से

घबराये हुए हैं ये लोग। जैसे ही हम लोगों ने ये तय किया, पूरी दिल्ली को इन्होंने गटर बनाके छोड़ दिया है, दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। पता नहीं क्या मुंह ले के दुनिया में जाते हैं? आप लंदन चले जाओ, चमाचम कर रहा है लंदन। वाशिंग्टन चले जाओ, चमाचम कर रहा है वाशिंग्टन। टोकियो चले जाओ, चमाचम कर रहा है टोकियो। पता नहीं, जब बराक ओबामा मिलता भी होगा तो कहता होगा कि तुम्हारी दिल्ली में आया था तो दिल्ली में तो बदबू आती है। क्या मुँह लेके ये पूरी दुनिया में जाते हैं ? बदबू ही बदबू आती है! पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ाघर बना रखा है एम.सी.डी. वालों ने। और लोगों को ये पता नहीं है। कई लोगों के फोन आते हैं कि आपकी सरकार बन गई फिर भी इतना कूड़ा? उनको बताना पड़ता है कि हमारी अंडर में नहीं है। एम. सी.डी. ये बी.जे.पी. वालों ने कबाड़ा कर रखा है, बी.जे.पी. वाले जितना पैसा देते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं ये बी.जे.पी. वाले! अभी दो बार पिछले एक साल में हड़ताल हुई सफाई कर्मचारियों की। कहते हैं, ''पैसे नहीं हैं तनख्वाह देने के लिए।'' पैसे नहीं हैं, तो जरा भी अगर गैरत बची है तुम्हारे अंदर तो इस्तीफा दे दो, भंग करो एम.सी.डी. को चुनाव करा लो। कल को अगर दिल्ली सरकार में बैठके मैं मुख्यमंत्री होके और ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होके अगर अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाएं, हम लोग तनख्वाह नहीं दे पायें अगर हम लोग, लानत है हमारे ऊपर! हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव हो जाने चाहिए और दुबारा जो तनख्वाह दिलवा सकते हों, उन लोगों को सरकार के अंदर आना चाहिए। कहते हैं, ''पैसा नहीं है हमारे पास तनख्वाह देने का।'' अरे ! पैसा नहीं है तो शर्म से डूब मरो, तुम लोग

अगर अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे सकते तनख्वाह का! एक गलतफहमी फैलायी गई कि पैसा दिल्ली सरकार नहीं दे रही, दिल्ली सरकार नहीं दे रही। मैं ये आपके सामने कुछ फीगर्स रखना चाहता हूं– ईस्ट एम.सी.डी. को 2013–14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने 416 करोड़ रूपये दिये, 2014–15 में जबकि बी.जे.पी. की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन था, उन्होंने 441 करोड़ रूपये दिये, 2015–16 में जब हमारी सरकार थी, हमने 702 करोड़ रूपये दिये, कांग्रेस ने 416 करोड़, बी.जे.पी. ने 441 करोड़, हमने 702 करोड़, लगभग दुगुने पैसे दिये हम लोगों, जितने बी.जे.पी. और कांग्रेस ने दिये। जब कांग्रेस की सरकार थी 2013–14 में तो तनख्वाह दे दी। तब तनख्वाह की प्रॉब्लम नहीं हुई। जब बी.जे.पी. की सरकार थी 2014–15 तब तनख्वाह दे दी। तब तनख्वाह की प्रॉब्लम नहीं हुई। 2015–16 में दुगुने पैसे दे दिये हमने, उनको तब भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। पैसा गया कहॉ? मन में प्रश्न उठता है! हमने दुगुने पैसे दे दिये तुमको, ऐसा तो है नहीं कि भई कर्मचारियों की नई भर्ती हुई हो, एक भी नई भर्ती नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि तुमने तनख्वाह बढ़ा दी उनकी। तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई तो ये सारा पैसा कहॉ गया? सारा पैसा खा गये ये लोग? सफाई कर्मचारियों के चुल्हे नहीं जल रहे और इनकी मर्सिडीज आ रही हैं! इन सारे काउंसलरों की, बड़े–बड़े बंगले बन रहे हैं! इनका सारा पैसा खा गए ये लोग। जितना पैसा हम लोग इनको तनख्वाह का देते हैं, सारा का सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। नॉर्थ एम.सी.डी. का डेटा बताता हूं। कॉग्रेस के टाईम में 2013–14 नॉर्थ एम.सी.डी. को 1051 करोड़ रूपये मिले कॉग्रेस, के टाईम में, 2014–15 में 848 करोड़ रूपये मिले बी.जे.पी. के टाईम में, और 2015–16 में जबकि

हमारी सरकार थी, हमने 1206 करोड़ रूपये दिये। 50 प्रतिशत हमने ज्यादा दिये बी.जे.पी. के टाईम से। बी.जे.पी. ने 848 करोड़ रूपये दिये थे। हमने 1206 करोड़... 50 प्रतिशत ज्यादा। गये कहां पैसे? सारा पैसा खा गये ये लोग! ये लोग कहते है कि हमने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया? ये पैसा आया है और ये पैसा सारे एम.सी.डी. कमिश्नर ने साइन कर रखा है कि ये पैसा मिला है, सारा पैसा, ये भ्रष्टाचार की वजह से इन लोगों ने पूरा डूबो दिया। जब पहली हडताल हुई थी तो मैं अरुण जेटली जी के पास गया था, मैंने अरुण जेटली जी को कहा कि आप सैंटर थोड़ा सा पैसा दे दो। बी.जे.पी. सैंटर में है, बी.जे.पी. एम.सी.डी. में है। आपकी अपनी पार्टी की सरकार है। एम.सी.डी. के अंदर तनख्वाह नहीं मिल रही हजार, डेढ़ हजार, दो हजार करोड़ रूपया उनको दे दो तो बोले कि हॉ, मेयर्स भी मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो भी पैसा मांग रहे थे। मैंने कहा, ''फिर दे दो।'' तो चुप हो गये वो। मैंने बाहर निकलके सोचा चुप क्यों हो गये वो? तो मेरे को लगा कि मोदी जी को और जेटली जी को भी एम.सी.डी. के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको पता है जितना पैसा देंगे, सारा खा जाएंगे ये लोग। इसलिए पैसा नहीं दिया उन्होंने। पैसा दे देते, अरुण जेटली जी के पास तो छ लाख करोड़ रूपये का बजट, 12 लाख करोड़ का बनाते हैं बजट। कितना पैसा है! उसमें से एक हजार करोड रूपया तो उनके लिए यूं चुटकी के बराबर है, दो मिनट में दे देते, दिया नहीं उन्होंने, उनको पता था, देने से कोई फायदा नहीं, इनको एक हजार करोड़ रूपये ओर दे दो, तनख्वाह फिर भी नहीं मिलनी। वो भी सारा पैसा खा

जाएंगे ये लोग। इसलिए जेटली जी ने इनको, इनकी अपनी बी.जे.पी. की सरकार जो बैठी है सैंटर के अंदर उनको भी भरोसा नहीं है इन लोगों के ऊपर। काला कुँआ बन गया है एम.सी.डी. जितना पैसा डालो, उतना पता ही नहीं चलता, कहॉ गया सारा? और इनसे जब भी पूछो? पैसा, पैसा पैसा, पैसा, इनसे पूछो, ''सफाई क्यों नहीं? पैसा, पैसा, पैसा, पैसा, अरे! सफाई के के लिए पैसा थोड़े चाहिए? एक झाड़ू उठाके सफाई करनी है, पैसा, पैसा, पैसा, पैसा, पैसा, पैसा, और पैसा! ऐसा पैसा? पैसे की ऐसी हाय लगी हुई है इन लोगों के अंदर कि जैसे पता नहीं, पैसे में मर मिटेंगे ये लोग! हर चीज में घोटाला! अभी मुझे कहने की जरूरत नहीं, इतने सारे हमारे विधायकों ने, इतने इग्जाम्पल अभी, वो अखिल बाहर चला गया, वो इतने कह रहा था, अभी शरद जी इतने इग्जाम्पल रहे थे, अलका लाम्बा जी ने, सबने इग्जाम्पल दिये, इतने उदाहरण दिये इन्होंने। एडवरटाईजमैंट के ऊपर ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल रेवेन्यू, ईस्ट दिल्ली का मतलब... हुआ वन थर्ड दिल्ली, एक तिहाई दिल्ली। एक तिहाई दिल्ली का एडवरटाईजिंग से एनुअल रेवेन्यू मात्र 12 करोड़ रूपये, 12 करोड़ रूपये का मतलब वन करोड़ पर मंथ। एक करोड़ पर मंथ का मतलब हो गया, जो होर्डिंग हैं हम नॉर्मली देखते हैं तीन–तीन लाख रूपये, चार–चार लाख रूपये की होती है। उसका एक लाख रूपया तो एम.सी.डी. को जाता ही होगा तो सौ होर्डिग, पूरी एक–तिहाई दिल्ली के अंदर 100 होर्डिंग हैं, बस! 100 होर्डिंग तो एन.एच. – 24 के ऊपर मिल जाएंगे आपको, तो कम से कम 5–7 हजार होर्डिंग होंगी, किसकी हैं वो होर्डिंग? इन एम.सी.डी. वालों की, काउंस्लरों की है, इन बी.जे.पी. वालों की होर्डिंग हैं, सारी चल रही है,

बी.जे.पी.–कॉग्रेस वालों के सारे ईल्लीगल होर्डिंग्स हैं। सारा पैसा खा रहे हैं ये लोग, पार्किंग, पार्किंग में मैंने इनका डेटा देखा। एक साल में सात करोड़ रूपये का टोटल रेवेन्यू ईस्ट दिल्ली का, सात करोड़ रूपये का। 365 दिन से डिवाईड कर लो, दो लाख रूपये पर–डे। दो लाख पर–डे का क्या मतलब हुआ? दो लाख रूपये तो एक मैट्रो की पार्किंग से निकल जाते हैं। एक मैट्रो की पार्किग में भी दो लाख रूपये से भी ज्यादा की ही कमाई... पूरी एक तिहाई। सारे ये पैसा पार्किग का खा जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं? नक्शे बनते हैं। एक नक्शा बनवाकर दिखा दो बिना पैसे के आज। मैं यहां मोदी जी को चैलेंज करता हूं, ''मोदी जी, आप अपने घर की छत बनवाकर एक छज्जा बनवाकर दिखवा दो आप अपने घर का। आपकी बी.जे.पी. है। एम.सी.डी. में, आपकी एम.सी.डी. है। फिर भी मैं चैलेंज करता हूं आप अपने घर का छज्जा बिना पैसे दिये बनवाकर दिखा दो, मैं राजनीति छोड दूंगा। अगर मोदी जी का भी छज्जा बिना पैसे के बन जाए तो!'' ये कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, राम चन्द्र जी की भी हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन आज साक्षात भगवान भी उतर पर आ जाए न, वो बिना पैसे के अपना घर नहीं बनवा सकते दिल्ली के अंदर। ये सैन्ट्रल इन्फोर्मेशन कमीशन ने एक आर्डर पास किया है। हम नहीं कर रहे... सीट पर चढ गए, सच्चाई झेलने की ताकत नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा था, मैं इस आर्डर के बेसिज पर.... केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह आर्डर पास किया है। इस आर्डर के तहत जो उन्होंने लिखा है। ये उन्होंने लिखा हैः "The Commission requires Mrs.Shobha Vijendra to explain to the Mayor and to her voters along with a copy of such explanation to this Commission why an ineligible applicant was recommended for the

pension in glaring violation of income norms and to assure the people that ineligible candidates do not be recommended in future. Such incidents should lead to introduce systems to make representatives of people including Councillors or Legislators to be brought under the purview of transparency law." उन्होंने लिखा हैः "Three MCDs should consult legal experts as to why this should not be considered as misappropriation of public moneyand why all those guilty including abettors through endorsements should not be prosecuted?" ये विजेन्द्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी के बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग ने लिखा है। हम नहीं कह रहे, केन्द्रीय सूचना आयोग कह रहा है कि विजेन्द्र गुप्ता जी की पत्नी के खिलाफ गबन का आरोप, उसका मुकद्दमा क्यों ने चलाया जाए? जो कि पार्षद हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आज अगर ए.सी.बी. हमारे पास होती, विजेन्द्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी जेल के अंदर होती। इनके सारे काउसंलर्स 2000–3000 रूपये महीना इनको तनख्वाह मिलती है और सब मर्सडीज में, ऑडी में, बड़ी–बड़ी गाडियों में घूमते हैं। कहां से आता है वो सारा.... कहां से आता है इतना पैसा इनके पास? बड़ी–बड़ी कोठियां बना ली इन्होंने! जनता पिसती जा रही है, जनता गरीब से गरीब होती जा रही है, सफाई कर्मचारी और गरीब होते जा रहे हैं, उनके चूल्हा नहीं जल रहा और इनके महल बनते जा रहे हैं, आज अगर एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती इनके 95 प्रतिशत काउंसलर्स जेल के अंदर बैठे होते, एम.सी.डी. खाली हो गई होती अभी तक। अब ये जो अभिलेखशपति त्रिपाठी ने दिखाया, अगर आज ए.सी.बी. हमारे पास होती, इनके पूर्व विधायक जितने भी थे बी.जे.पी.

और कांग्रेस के, उनमें से आधे से ज्यादा चक्की पीस रहे होते जेल के अंदर। अगर एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास होती! इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है इनके यहां तो भ्रष्टाचार की वजह से इन्होंने खत्म कर दिया पूरा एम.सी. डी. को। लेकिन जो कुछ इन्होंने कल किया रामलीला मैदान में, वो बहुत ही घिनौना है। मैं ये इस लिए नहीं कह रहा, वो हमारा कांउसलर था, किसी भी का भी काउंसलर हो, इंसान था वो। जिस तरह से उसको पीटा गया, ये कोई शोभा नहीं देता। ये गलत है। आप पूरी वीडियो देखो। एक गलतफहमी फैलायी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उसको टोपी की वजह से पीटा। टोपी की वजह से नहीं पीटा। उसकी टोपी उतार ली। वो सोफे पर बैठा हुआ, तीन चार और बैठे हुए हैं, टोपी उतारने के बाद बातचीत चल रही है। फिर उसको उठाकर पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति को अपने साथ बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। वो एक दलित को अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। वही छुआछूत की मानसिकता इन बी.जे.पी. के लोगों के अंदर है। उनको यह लग रहा है कि एक दलित हमारे साथ बैठ कैसे गया? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये काउंसलर चुनकर आ गया और हमारे साथ बैठ गया ! मैं यह सोच रहा था कि जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई है, जिस तरह से उसको पीटा गया, उसकी मानसिकता क्या होगी उस टाईम उस व्यक्ति की? जिस तरह से उसको धिक्कार कर के? जिस तरह से उसके साथ बेइज्जती की गई, उसका अपमान किया गया, उसका सम्मान रौंदा गया। आप उसकी मनोदशा समझने की कोशिश कीजिए उस व्यक्ति की। जिस तरह से उसका अपमान किया गया वहां पर। रोहित बेमूला को इन लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर

कर दिया! पूरे देश के अंदर जब से बी.जे.पी. की सरकार बनी है चुन–चुन कर माईनॉरिटीज को और दलित की प्रताड़ना की जा रही है। उनको गुंडागर्दी के तहत पीटा जा रहा है। उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नफरत करती है बी.जे.पी. दलितों से, नफरत करती है बी.जे.पी. मुसलमानों से, नफरत करती है बी.जे.पी. क्रिश्चियन्स से, नफरत करती है बी.जे.पी. सिक्खों से, नफरत करती है बी.जे.पी. माईनॉरिटीज और दलितों से। इनका, बी.जे.पी. वालों का बस चले तो दलितों को, माईनारिटीज को उठाकर प्रशान्त महासागर में फैंक दे ये लोग! ये तो एम.एम. खान के साथ जो हुआ... ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान है जो इनको ये करने नहीं दे रहा। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता! ये बी.जे.पी. वाले दलितों और माईनॉरिटीज को उठाकर प्रशान्त महासागर में फैंक चुके होते। बाबा साहब अम्बेडकर को सैल्यूट करते हैं हम लोग। जिन्होने ये संविधान बनाया और जिसकी सुरक्षा की वजह से, जिसके प्रोटेक्शन की वजह से आज ये लोग ये नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं बी.जे.पी. को चेतावनी देता हूं, ''आप लोगों के मन ये घिनौनी बातें होंगी, इस देश के लोगों के मन में न जात है, न धर्म है, इस देश के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग भारतीय हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं और अगर तुमने अपनी हरकत नहीं बदली तो इस देश के सारे लोग मिलकर तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगें, तुमको नेस्तानाबूद कर देगें। आज दो किस्म की राजनीति इस देश के अंदर सामने आ रही है। एक वो राजनीति है बी.जे.पी. वालों की जब वो दलितों की पिटाई कर रहे हैं दलितों को अपमानित कर रहे हैं, और दूसरी वो राजनीति आम आदमी

पार्टी की जो दलितों को सम्मान देती है, बराबरी का हक देती है। आज ही का दिन है जब हमारी बहन उपाध्यक्ष बनी हैं इसी सदन की। दलितों को बराबरी का हक दिया जा रहा है। ये दो किस्म की राजनीति आज इस देश के अंदर सामने आई है। लीडर आफॅ ओपोजिशन ने आज जिस तरह की हरकत की। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाउस जनतंत्र का मंदिर है। इसका सम्मान करना हम सब लोगों का धर्म है। देश के लोगों का धर्म है। हमारे यहां हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, हमारा धर्म है। जिस तरह से वो चढ गए इसके ऊपर, मैं सोच रहा था, ''वहां कागज भी पडे होंगे, कागजों के ऊपर भी चढ गए !'' जब हम बच्चे थे, सिखाया जाता था कि कागज पर पैर लग जाता था है तो उसको चुचुकार लिया करते थे हम लोग। उसके ऊपर चढ गए! न वो विद्या की, सरस्वती की वो चिंता करते! न हाउस की चिंता करते! किसी चीज की वो चिंता नहीं करते! उन्होंने जिस तरह का अपमान किया है इस सदन का, इससे जनतंत्र शर्मसार हुआ है। अंत में संविधान शर्मसार हुआ है ! अभी जब मैं बाहर गया तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ए.सी. बी. वाले एफ.आई.आर. करने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या हो गया, तो पता चला कि मोदी जी देश लौट आएं हैं। मोदी जी के पास दो ही काम हैं– या तो विदेशों में घूमते रहते हैं, और जैसे ही देश लोटते हैं उनको हम ही दिखाई देते हैं। तो पता चला कि मोदी जी देश लौट आएं है और अब हमारे खिलाफ एफ.आई.आर. करेगें। पता चला कि गोपाल राय जी को सम्मन करने तैयार हो रही हैं। तो मैं गोपाय राय जी से तो निवेदन करूंगा कि वो बेचारे सम्मन करने की इतनी जहमत करें, इससे

अच्छा आप ही अपने सारे अफसरों को, सारी फाईलों को लेकर सोमवार को ए.सी.बी. के यहां पहूंच जाना। या मोदी जी को चिट्ठी लिखकर पूछ लेना कि बताओ जी कहां जाना है? आप क्यों तकलीफ करते हो ? हम ही आ जाते हैं। आप खुद ही चले जाना। मनीष से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने आप ही सारे अफसरों को लेकर पहूंच जाना वहां पर। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, फौलाद के बने हैं, इन गीदड़ भभकियों से... तुम्हारी ये सी.बी.आई.–फी.बी.आई., ए. सी.बी.–फेसी.बी, इनसे डरने वाले नहीं हैं हम लोग। ये अपने घर रखना। ऐसी बहुत काट कर आएं है। अन्ना जी कहा करते थे न– जो लोग गलत काम करते हैं, उनके लिए जेल दूषण है, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आजादी के लडाई लडते हैं, उनके लिए जेल आभूषण है। तो गलत तो एल.जी साहब और मोदी साहब कर रहे हैं। वो जेल जाएंगे, उनके लिए दूषण है। हम सच्चाई के रस्ते चले रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए... हम को सौ बार जेल भेज लो, हम को जेल जाने से डर नहीं लगता। हमारे लिए जेल भूषण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः मुझे माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती जी से एक प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के दषष्टिगत मैंने इस नोटिस को स्वीकार किया है। मैं, सोमनाथ भारती जी से प्रार्थना करता हूं। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने कि अनुमति मांगे।

श्री सोमनाथ भारतीः Hon'ble Speaker, Sir, I wish to seek the permission to place this version in the House.

अध्यक्ष महोदयः अनुमति दी जाती है।

श्री सोमनाथ भारतीः Hon'ble Speaker, Sir, the motion which I wish to move, I thank you for having accorded your permission to place this motion. I'll read the motion, Sir.

"That a House Committee be constituted to enquire into alleged rampant corruption and irregularities in the Municipal Corporations of Delhi."

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव जो सोमनाथ जी का है, अब सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं वो न कहें।

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्षे महोदयः अब सोमनाथ जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने कि अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सोमनाथ भारतीः Hon'ble Speaker, Sir, I am thankful to you and to the House for having agreed to allow me to move this motion. Motion is the following:

"that a House Committee be constituted to enquire into alleged rampant corruption and irregularities in the Municipal Corporations of Delhi and to suggest measures for improvement in their functioning. That the Committee shall consist of the following members: Sh.Ajesh Yadav, Sh. Kartar Singh Tanwar, Sh. Mahender Yadav, Sh. Naresh Balyan, Sh. Rajesh Gupta, Sh. Sahi Ram, Sh. Sharad Kumar, Ms. Bhavna GaurAnd Sh. Jagdish Pradhan."

I had a word with Sh. Jagdish Pradhan Ji on phone and he has agreed to be a member. So, I thank you for a greeing with this. That the Hon'ble Speaker shall appoint one of the members, in fact, he was saying that कि पता नहीं पार्टी हमारी राजी हो कि नहीं होगी। लेकिन क्या कहते हैं मैंने कहा कि भाई आप देखो। भ्रष्टाचार की बात है ये। तो चलिए आप कहते हैं तो हो जाते हैं। ये हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो राजी हुए।

that the hon'ble Speaker shall appoint one of the members of the Committee as its Chairperson. That the terms of reference of the Committee shall be as under:

1. to enquire into the allegations of rampant corruption and irregularities in the Municipal Corporations of Delhi.

2. to study the existing set up of the Municipal Corporations in Delhi and to recommend measures to improve its functioning in all spheres includingAdministration, sanitation, primary health and education, service delivery system, revenue generation, financial sustainability etc.

3. To studyand recommend about the suitability of continuing with present set up of three Municipal Corporations.

4. To receive and enquire into complaints and representations from various stakeholders and general public on issues pertaining to the Municipal Corporation and recommend corrective measures; and

5. to take upAny other matter that incidental or consequential to the issue under examination.

6. that the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House.

7. the the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed subject to the approval of hon'ble Speaker.

8. that the Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing committees of the legislative Assembly; and

9. that the Committee shall submit its report to hon'ble Speaker before the commencement of the Sixth Session of the Sixth Legislative Assembly.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत तथा संशोधित प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदयः सदन का काफी कामकाज अभी लंबित है। कल भी और आज भी नेता विपक्ष द्वारा सदन का काफी समय जो बहुमूल्य था, बर्बाद हुआ है और इसलिए काफी काम अभी लंबित रह गया है। मैं, सदन से सहमति चाहता हूं कि एक दिन ओर सदन का सत्र बढ़ाया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। एक दिन के समय बढ़ाने के लिए आप सब के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

सदन की सहमति मिली। अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 13 जून, 2016 अपराह्न 2:00 बजे तक स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।